

अपने छोटे-छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है।

03 मतदाता सूची में इस तरह शामिल कराएं अपना नाम...

06 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़ने का परिदृश्य

08 केन्द्र सरकार के हॉस्पिटल में अब होगी डॉक्टर की कमी

## डाइविंग लाइसेंस में होगा बड़ा बदलाव? CJI चंद्रचूड़ की बेंच में आया ये सवाल, केंद्र ने तुरंत दिया जवाब



### संज्ञ बाटला

नई दिल्ली। दरअसल, केंद्र के नोट में यह संकेत दिया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए परामर्श में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आम चुनाव के बाद नवम्बर 2024 के संसद के सत्र में इसे पारित किया जाएगा। क्या हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए डाइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है, जिस पर कोई सामान

नहीं लदा हो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष मंगलवार को यह मामला सामने आया। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अर्दानी जनरल आर वेंकटरमणी ने एक नोट प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले को स्थगित कर दिया। अब इस केस की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। दरअसल, इस नोट में यह संकेत दिया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए परामर्श में मोटर वाहन

अधिनियम, 1988 में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आम चुनाव के बाद नवम्बर 2024 के संसद के सत्र में इसे पारित किया जाएगा। पीठ ने कहा, "मंत्रालय ने अपने 15 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से कानून में प्रस्तावित संशोधन का ब्योरा रिकॉर्ड पर रखा है।" पीठ ने न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति पी एस केस की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। दरअसल, इस नोट में यह संकेत दिया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए परामर्श में मोटर वाहन

होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था और नियमों में संशोधन किया गया था। मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिसका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, को एलएमवी (हल्के मोटर वाहन) की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।

## दिल्ली परिवहन आयुक्त ने आटो में जीपीएस नेविगेशन ट्रैकिंग की आवश्यकता को सिरे से नकारा, जाने

### परिवहन विशेष न्यूज

दिनांक 22/04/2024 को दिल्ली परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहित कई आला अधिकारियों के साथ दिल्ली के लगभग 2 दर्जन ऑटो रिक्शा यूनियन एग्रेसिवेशन के पदाधिकारियों के साथ एक सांझा बैठक हुई जोकि आटो में सीम और डिम्पस नहीं लगाने के संबंध में था। सभी यूनियनो के पदाधिकारियों ने एक स्वर में आटो में सीम व डिम्पस नहीं लगाने का आग्रह किया और कमिन्शनर साहब ने यूनियनो की मांग को मान लिया और कहा कि आटो में सीम व डिम्पस की कोई आवश्यकता नहीं, आटो में सीम व डिम्पस नहीं लगाना, हालांकि सीम व डिम्पस कंपनी के अधिकारियों ने आटो चालकों को बंदनाम करने की बहुत कोशिश की, कि आटो वाले मीटर से नहीं चलते, सवारियों से मुंह मांगा पैसे मांगते हैं इसलिए आटो में सीम व डिम्पस लगाना चाहिए,



जिसका भी विरोध करते हुए यूनियनो ने कहा कि ये मामला दिल्ली परिवहन विभाग और आटो चालकों के बीच का है आटो चालकों को इस तरह बंदनाम करके कंपनीयां लुट नहीं मचा सकती। आयुक्त साहब ने यूनियनो की बात को मानते हुए, सीम व डिम्पस कंपनीयां के अधिकारियों

की आरोपो को सिरे से खारिज कर दिया। इसके लिए सभी अधिकारियों एवं यूनियनो के पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए दिल्ली के समस्त आटो चालकों को हार्दिक बधाई देते हैं।  
सुभाष कुमार, (महासचिव राष्ट्रवादी जन चेतना समिति)

## कुछ हवाई रुटों पर टिकटें उपलब्ध है मात्र 150 रुपए में

### परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हवाई जहाज से उड़ना आज भी करोड़ों भारतीयों का सपना है। मगर, महंगे टिकट के कारण कई लोग हवाई जहाज में सफर नहीं कर पाते हैं। हालांकि, आज हम आपको ऐसे हवाई रूट की जानकारी देने जा रहे हैं, जहां आप सिर्फ 150 रुपये मूल किराए में सफर कर सकते हैं। सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा मगर, यही सच है। असम में लीलाबाड़ी से तेजपुर तक 50 मिनट की हवाई सेवा ले सकते हैं। चलिए जानते हैं रूट के बारे में- लीला बाड़ी से तेजपुर के बीच हवाई सफर कराने पर मूल किराए के रूप में सिर्फ 150 रुपए देना पड़ता है। दोनों शहरों के बीच का हवाई सफर केवल 50 मिनटों में तय कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कई उड़ानें हैं, जहां टिकट का मूल किराया 1 हजार रुपए से भी कम है। ये सभी क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत संचालित होते हैं। 22 रूट पर 1 हजार रुपए से कम किराया ट्रेवल पोर्टल इक्सिगो की रिपोर्ट के अनुसार कम-से-कम 22 रूट हैं, जिन पर मूल हवाई किराया 1 हजार रुपए प्रति व्यक्ति से कम है। असम में लीलाबाड़ी और तेजपुर को जोड़ने वाली उड़ानों के लिए एक ओर का किराया सबसे कम 150 रुपए है। इस रूट पर उड़ानों का संचालन अलायंस एयर करती है। टिकट केवल बुक करते समय मूल किराए में सुविधा शुल्क भी जोड़ दिया जाता है। अधिकतर रूट पर किराया 150-199 रुपए रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण में बंगलुरु-सलेम, कोचीन-सलेम जैसे मार्ग हैं जहां मूल टिकट की कीमतें 1 हजार रुपए से कम हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यह उन मार्गों में से हैं, जहां मांग कम है। साथ ही अन्य परिवहन माध्यमों से इन जगहों पर पांच घंटे से अधिक



समय में पहुंचा जा सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के मुताबिक 31 मार्च तक क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक) के तहत 559 मार्ग चिह्नित हैं। उड़ानों के लिए 'लैंडिंग' या 'पार्किंग' चार्ज नहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा परिचालक

क्षेत्रीय उड़ान सेवा के तहत उड़ानों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन देते हैं। इन उड़ानों के लिए 'लैंडिंग' या 'पार्किंग' चार्ज भी नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को प्रोत्साहित करने एवं हवाई यात्रा को और किफायती बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 2016 को उड़ान सेवा शुरू की थी

## दिल्ली मेट्रो में मछरो द्वारा उत्पात, क्या मेट्रो प्रशासन इसका कोई हल करेगा ?....

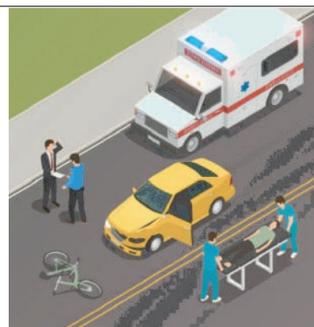
राजकल दिल्ली मेट्रो के अंदर के कई तरह की गैर विडियो विलय सोशल मीडिया पर वायरल होते आ रहे हैं। अब एक नया विडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेट्रो में मछरो से परेशान यात्रियों को देखा जा सकता है। यह विडियो उदखने के बाद लोग मेट्रो की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यह वायरल विडियो ग्रे (ट्रारका- नज़फ़गढ़- डांडा बाईर) कोटिडर का बताया जा रहा है। वायरल विडियो में दिखा रहा है कि कैसे चाली मेट्रो में मछरो से यात्री परेशान है। विडियो में यात्री, गमछे, रुग्नाल और हाथों से मछरो को गंजाते दिख रहे हैं। ऐसे इन दिनों पूरी दिल्ली में मछरो का आतंक बढ़ा हुआ है। इस वजह से शाम होते ही मछरो से परेशानी बढ़ जाती है। मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का गेट खुलने के दौरान मछरो मेट्रो में प्रवेश कर जाते हैं। पहले भी ग्रे ट्रांसपोर्ट व इंडस्ट्री से युग्वा बैंक स्टेशन के बीच मेट्रो में मछरो की परेशानी की बातें सामने आ चुकी हैं। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मछरो की उत्पत्ति रोकने कि लिए अरुची कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ग्रे ट्रांसपोर्ट मेट्रो में मछरो के आतंक से यात्री परेशान, क्या मेट्रो प्रशासन इसका कोई हल निकालेगा ??



## सड़क सुरक्षा पाठशाला : सड़क दुर्घटनाएँ: उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मार्गदर्शिका

### परिवहन विशेष

सड़क दुर्घटनाएँ कष्टदायक और भारी हो सकती हैं, लेकिन तत्काल परिणाम में क्या करना है यह जानने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है:  
**शांत रहें:** चाहे यह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, शांत रहने का प्रयास करें। अपने आप को स्थिर करने के लिए कुछ गहरी साँसें लें और शांति से स्थिति का आकलन करें।  
**सुरक्षा सुनिश्चित करें:** यदि संभव हो, तो आने वाले यातायात से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। अन्य ड्राइवर्स को सचेत करने के लिए मामूली लंगे, तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है।  
**अधिकारियों को कॉल करें:** दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से संपर्क करें। उन्हें स्थान, शामिल वाहन की संख्या और किसी भी चोट के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करें।  
**जानकारी का आदान-प्रदान:** दुर्घटना में शामिल अन्य पक्ष/पार्टियों के



साथ संपर्क और बीमा विवरण का आदान-प्रदान करें। नाम, पता, फ़ोन नंबर, लाइसेंस प्लेट नंबर और बीमा जानकारी नोट करें।  
**दृश्य का दस्तावेजीकरण करें:** वाहन की क्षति, सड़क की स्थिति और किसी भी प्रासंगिक संकेत सहित दुर्घटना स्थल की तस्वीरें लें। यह दस्तावेज बीमा दावों और कानूनी कार्यवाही के लिए अमूल्य हो सकता है।  
**गलती स्वीकार करने से बचें:** गलती स्वीकार करने या घटनास्थल पर दाय्ये महने से बचें। सबूतों के आधार पर दोष्य निर्धारित करने का काम अधिकारियों और बीमा कंपनियों पर छोड़ दें।  
**अपनी बीमा कंपनी को सूचित करें:** दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए

जितनी जल्दी हो सके अपने बीमा प्रदाता से संपर्क करें। उन्हें सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करें और उनकी जांच में पूरा सहयोग करें।  
**यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह लें:** यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षति, चोट या विवाद होता है, तो व्यक्तिगत चोट या यातायात कानून में विशेषज्ञता वाले कानूनी पेशेवर से परामर्श लेने पर विचार करें। वे आपके अधिकारों और विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।  
**अनुवर्ती कार्रवाई:** किसी भी चल रहे उपचार या पुनर्वास के लिए चिकित्सा पेशेवरों से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका दावा सुचारू रूप से आगे बढ़े, अपनी बीमा कंपनी के साथ संपर्क में रहें।

**अपना खयाल रखें:** सड़क दुर्घटना से निपटाना भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों, परिवार या परामर्शदाता से सहायता लेने में संकोच न करें। इन चरणों का पालन करके, आप सड़क दुर्घटना के बाद अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। याद रखें, सड़क पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा और भलाई हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।  
डॉ अंकुर शरण, राष्ट्रीय मुख्य यातायात एवं नियोजन अधिकारी (Road Safety Omni Foundation)

## सड़क सुरक्षा पाठशाला - प्रेशर हॉर्न : सड़क सुरक्षा के लिए खतरा

शहरी जीवन के शोर-शराबे में, प्रेशर हॉर्न हमारी सड़कों की अवांछित ध्वनि बन गए हैं। हालांकि शुरुआत में इसका उद्देश्य दूसरों को सचेत करना एक सुरक्षा उपाय था, लेकिन उनके दुरुपयोग ने उन्हें एक महत्वपूर्ण खतरों में बदल दिया है। प्रेशर हॉर्न की लगातार बजने वाली आवाज न केवल हमारी इंद्रियों पर हमला करती है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। प्रेशर हॉर्न के साथ प्राथमिक समस्याओं में से एक उनका अंधाधुंध उपयोग है। डाइवर अक्सर इन्हें अनवांछित रूप से तैनात करते हैं, चाहे निराशा व्यक्त करने के लिए, प्रभुत्व का दावा करने के लिए, या केवल शोर मचाने के रोमांच के लिए। ध्वनि की यह निरंतर बीछार पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और अन्य ड्राइवर्स को चौंका सकती है, जिससे दुर्घटनाएँ हो सकती हैं और सड़क पर तनाव का स्तर बढ़ सकता है। इसके अलावा, प्रेशर हॉर्न ध्वनि प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय



तक तेज आवाज के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता में कमी, नींद में खलल, हृदय गति में वृद्धि और यहां तक कि संज्ञानात्मक हानि भी हो सकती है। कमजोर आबादी जैसे बच्चे, बुजुर्ग और संवेदी संवेदनशीलता वाले व्यक्ति विशेष रूप से इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रेशर हॉर्न हमारे आसपास के

प्राकृतिक ध्वनि परिदृश्य को बाधित करते हैं, जिससे आपातकालीन वाहन सायरन, पैदल यात्री अलर्ट और आने वाले वाहनों जैसे महत्वपूर्ण श्रवण संकेतों को सुनना मुश्किल हो जाता है। यह स्थितिजन्य जागरूकता से समझौता करता है और सड़क पर संभावित खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता को खराब करता है।

इन जोखिमों को कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेशर हॉर्न के उपयोग को विनियमित करना आवश्यक है। जन जागरूकता अभियानों के साथ मौजूदा ध्वनि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू करने से उनके दुरुपयोग को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, शांत हॉर्न या हॉर्न-मुक्त वाहनों जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों में

निवेश हमारी सड़कों पर शोर के स्तर को कम करने के लिए व्यवहार्य समाधान प्रदान कर सकता है। प्रेशर हॉर्न का प्रसार सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। प्रभावी विनियमन के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित करके और जिम्मेदार ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देकर, हम अपनी सड़कों को सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण स्थान के रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रेशर हॉर्न के खतरों को शांत करने और एक शांत, सुरक्षित भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करने का समय है। जो ड्राइवर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करता है उसे यह जानना जरूरी है कि इसके लिए मोटर वाहन नियम में चालान का प्रावधान है और साथ ही परमिट कंडीशन का भी चालान बनता है यानी 66/192A लगा कर मालिक और चालक दोनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। डॉ अंकुर शरण राष्ट्रीय मुख्य यातायात एवं नियोजन अधिकारी (Road Safety Omni Foundation)

## देवेन्द्र सिंह, सदस्य स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोड सेफ्टी कमेटी भारत सरकार की जनता से अपील



### परिवहन विशेष न्यूज

कृपया इन 9 बातों का सदैव याद रखें और यातायात नियमों का पालन करें, गलत दिशा में वाहन पार्क ना करें, वाहन में सीट बेल्ट लगा कर बैठें, वाहन चलते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, लाल बत्ती पर को पार ना करें, निजी नम्बर के वाहन से व्यवसायिक गतिविधि ना करें, नशा करके वाहन ना चलाए, तय गति सीमा से तेज वाहन ना चलाए, सामान ढोने वाले वाहन पर सवारी ना बैठाए, दो पहिया वाहन पर हेलमेट पहने, अगर आप ने इन बातों पर सड़क पर चलते समय अमल नहीं किया और इनमें से किसी नियम का भी सड़क पर चलते

समय उल्लंघन किया तो ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग प्रवर्तन शाखा राज्य एवं भारत सरकार आपका चालान काट सकता है और आपका डाइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में पहले से 10 गुना जुर्माना हो चुका है। आपकी जानकारी हेतु बता दें कि अब जरूरी नहीं है कि आपकी गलती के लिए आपको सड़क पर रोककर चालान किया जाए अब चालान सीसी टीवी के माध्यम एवं पुलिस के सड़क पर फोटो खींचने से भी आ सकता है। इसलिए सड़क पर सावधानी से चलें और ट्रैफिक के नियमों का हमेशा पालन करें। पुलिस एवं प्रशासन को हमेशा सहयोग करें। \*सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा स्पेशल नोट: कृपया आप ट्रैफिक के नियमों की जानकारी अपने जानकारों, रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों से शेयर करें।



# डीयू के छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर, 'समर इंटरशिप योजना' के लिए चार मई तक करें आवेदन; हर महीने कमाई का मौका

समर इंटरशिप हर हफ्ते 20 घंटे की होगी और हर महीने विद्यार्थियों को 10500 रुपये स्टैण्डिंग दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले ही इस इंटरशिप का लाभ ले लिया है वे इसके आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इंटरशिप के समापन के बाद विद्यार्थियों को अधिष्ठाता छात्र कल्याण की ओर से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए विद्यार्थी चार मई तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहां के विद्यार्थियों के लिए दो महीने की अवधि की समर इंटरशिप योजना लाया है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर में नियमित तौर पर पढ़ाई करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। अधिष्ठाता छात्र कल्याण की ओर से इंटरशिप का हिस्सा बनने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जून और जुलाई में होने वाली इंटरशिप योजना के लिए अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।

समर इंटरशिप हर हफ्ते 20 घंटे की होगी और हर महीने विद्यार्थियों को 10500 रुपये स्टैण्डिंग दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले ही इस इंटरशिप का लाभ ले लिया है, वे इसके आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इंटरशिप के समापन के बाद विद्यार्थियों को अधिष्ठाता छात्र कल्याण की

ओर से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए विद्यार्थी चार मई तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

**अनुशंसा पत्र लेकर ऑनलाइन जमा करना होगा**

जो भी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने प्राचार्य या विभाग प्रमुख से अनुशंसा पत्र लेकर ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बिना उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अनुशंसा पत्र का इंटरशिप के लिए साक्षात्कार के दौरान भी दिखाया होगा।

स्टूडेंट्स का चुनाव अनुशंसा पत्र और साक्षात्कार और सामूहिक चर्चा के बाद किया जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थी को कुलपति, उपकुलपति, डीन ऑफ कॉलेज, दक्षिण परिसर के निदेशक, नियंता कार्यालय, अधिष्ठाता छात्र

कल्याण, कुलसचिव कार्यालय में काम करने का मौका दिया जाएगा। केंद्रीय पुस्तकालय, विज्ञान पुस्तकालय, विभागों के पुस्तकालय, विभागों की प्रयोगशाला में भी इंटरशिप होगी।

**2022-23 से 'वाइस चांसलर इंटरशिप योजना' शुरू**

परीक्षा विभाग, प्रवेश शाखा, शोध परिषद, खेल परिषद के अलावा क्लस्टर इन्वेंशन सेंटर, ईस्टस्ट्र्यूट आफ लाइफ लॉग लॉनिंग, महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र, वैश्विक अध्ययन केंद्र, स्कूल आफ ओपन लॉनिंग (एसओएल) और एनसीवेब में भी काम करने का मौका मिलेगा। पिछले साल इस योजना के लिए सात हजार आवेदन किए गए थे। जिनमें से सौ छात्रों का चुनाव किया गया था। डीयू ने सत्र 2022-23 से 'वाइस चांसलर इंटरशिप योजना' शुरू की थी।

## इंसुलिन की मांग पर CM केजरीवाल को लगा झटका, डॉक्टर के साथ रोज 15 मिनट VC की इजाजत वाली याचिका खारिज

दिल्ली की अदालत ने सीएम केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को इंसुलिन देने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने शुगर लेवल के घटने-बढ़ने के संबंध में रोज 15 मिनट के लिए डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श देने की अनुमति देने की मांग की थी।



निर्णय

उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड को यह तय करना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड एक निर्धारित आहार और एक्सरसाइज प्लान पर भी निर्णय लेगा, जिसका नियमित पालन किया जाना चाहिए। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आहार योजना में कोई बदलाव नहीं होगा।

**19 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित**

बता दें, सीएम केजरीवाल ने इंसुलिन देने और रोज 15 मिनट वीसी के जरिए डॉक्टरों परामर्श की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। 19 अप्रैल (शुक्रवार) को इस पर सुनवाई हुई और विशेष जज ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केजरीवाल 22 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित हैं और उन्हें रोज इंसुलिन की जरूरत होती है।

## आग लगने पर गोपाल राय ने मांगी रिपोर्ट, 48 घंटे का दिया समय; ऐसी घटनाएं रोकने का भी मांगा प्लान



दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग को गाजीपुर लैंडफिल साइट (Ghazipur Landfill Site) पर लगी आग के कारणों और गर्मी के मौसम में ऐसी साइटों पर इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कार्ययोजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। गोपाल राय द्वारा जारी आदेश में पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव को 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग को गाजीपुर लैंडफिल साइट (Ghazipur Landfill Site) पर लगी आग के कारणों और गर्मी के मौसम में ऐसी साइटों पर इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कार्ययोजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

कैबिनेट मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी आदेश में पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव को 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि रविवार शाम को गाजीपुर

लैंडफिल साइट पर बड़े पैमाने पर लैंडफिल में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे आसपास के इलाकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण विभाग संभालने वाले राय ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट में आग के कारण से संबंधित सभी पहलुओं और इसका मुकाबला करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए तत्काल कदमों को शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "पिछले वर्षों के दौरान भी आग लगने की घटनाएं घटनाएं सामने आई थीं। मौका मुआयना करने के बाद मैंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।"

आदेश में कहा गया, रविवार ने ऐसी घटनाओं को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐसे दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में सभी संबंधितों से एक रिपोर्ट एकत्र की जाए। इसने गर्मी के मौसम के दौरान दिल्ली में सभी लैंडफिल साइटों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विभाग को कार्य योजना पर विवरण भी मांगा।

## तिहाड़ में केजरीवाल के इलाज के लिए गठित होगा मेडिकल बोर्ड, आतिशी और सौरभ भारद्वाज की रही ये प्रतिक्रिया

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज के राज एग्ज्यूटिव कोर्ट के आदेश से साबित होता है कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं उन्हें सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड आज ही बैठेगा और अरविंद केजरीवाल का चेकअप करेगा और उन्हें इंसुलिन देना शुरू कर देगा।

**नई दिल्ली।** दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल की इंसुलिन देने और डॉक्टरों परामर्श की मांग की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को केजरीवाल को उचित इलाज देने की व्यवस्था करने की कहा और केजरीवाल के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर आप नेताओं की प्रतिक्रिया आई है।

दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने दिल्ली कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि उन्हें आज से ही इंसुलिन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुगर लेवल 300 ऊपर जाने



के बाद इंसुलिन दिया जाना ही एकमात्र उपाय है।

**बीते 22 दिन से उन्हें उचित इलाज नहीं मिला**

उन्होंने कहा, 8 आज के राज एग्ज्यूटिव कोर्ट के आदेश से साबित होता है कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, उन्हें सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। हमें उम्मीद है कि ये मेडिकल बोर्ड आज ही बैठेगा और अरविंद केजरीवाल का चेकअप करेगा और उन्हें इंसुलिन देना शुरू कर देगा।

**जेल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था; सौरभ**

वहीं, दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अरविंद केजरीवाल करीब 22 दिनों से तिहाड़

जेल में हैं। वह कई दिनों से कह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है और जेल के अंदर कोई विशेषज्ञ मधुमेह विशेषज्ञ नहीं है और वह इंसुलिन की मांग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जेल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था।

उन्होंने कहा कि आज कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि तिहाड़ जेल में कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट नहीं है। मधुमेह विशेषज्ञों के साथ एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, जो यह तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या इलाज दिया जाना चाहिए और कौन सी दवा की आवश्यकता होनी चाहिए।"

## गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग कब मिलेगी दिल्ली को इन कचरे के पहाड़ों से मुक्ति

परिवहन विशेष न्यूज

**गाजीपुर।** लैंडफिल साइट पर आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। रविवार शाम को लैंडफिल के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। हवा चलने की वजह से धुआं छह किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी व आंखों में जलन होने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की नौ गाड़ियां लैंडफिल साइट पर पहुंचीं। दमकल व निगम की टीमें मशीनों के जरिये आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। खबर लिखे जाने तक आग लगी हुई थी। मीथेन गैस हो सकती है वजह आशंका है कि मीथेन गैस की वजह से आग लगी। आग खुद लगी या फिर किसी ने लगाई है। निगम व पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल ने साइट का निरीक्षण भी किया। दोपहर से धुआं उठना हुआ शुरू लैंडफिल साइट पर दोपहर से कूड़े से धुआं उठाना शुरू हो गया था। शाम होते ही आग भड़क गई और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी। शाम 5:22 बजे दमकल को आग की सूचना दी गई। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं आइपीएक्सटेशन, गाजीपुर, मयूर विहार, खोड़ा, इंदिरापुरम तक फैल गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन होने लगी। धुआं बढ़ने पर लोगों ने छोड़ा घर इस समस्या से एनएच-नौ समेत आसपास की



सड़कों पर वाहन चलाने वाले चालकों को भी जूझना पड़ा। धुआं बढ़ने पर गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मुल्ला कॉलोनी के कई लोग घरों को बंद करके दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। कई किमी दूर रहने वाले भी परेशान मुल्ला कॉलोनी में रहने वाले बिलाल अंसारी ने बताया कि एक वर्ष में कई बार लैंडफिल पर आग लगती है। इसके आसपास रहने वाले तो छोड़िये कई किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी लैंडफिल साइट से परेशान हैं। यहां फूड़े में एक बार आग लगने पर उसपर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, कई दिनों तक लगी रहती है। धुएं के कारण लोगों की आंखों से पानी निकलना रहता है। सांस लेने के लिए मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाना पड़ता है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के एक छोटे से पैच ने आग पकड़ी थी। निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को मौके पर भेज दिया गया था। स्थिति

निंत्रण में है। -शैली ओबेराय, महापौर, दिल्ली नगर निगम। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आगजनी का मामला सामने आने के बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आग पर जल्द काबू पाने के निर्देश दिए। गर्मी और मौसम में झड़नेस की वजह से आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए 5 एक्सकवेटर और अधिक दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं - आले मोहम्मद इकबाल, उपमहापौर, दिल्ली नगर निगम। दिल्ली लंदन तो नहीं बनी, लेकिन कूड़े के पहाड़ों पर एक बार आग लगी है राष्ट्रीय राजधानी को राख बनाकर ही छोड़ेगी। गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग का वीडियो खोजफनाक है। अब तो आप ही निगम में है। अब वह इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे।

-**भाजपा, दिल्ली प्रदेश**  
लैंडफिल का हिस्सा गिरने से हुई थी दो लोगों की मौत गाजीपुर लैंडफिल साइट के

पास एक नाला व नदी है, दोनों के बीच सड़क है। सितंबर 2017 में गाजीपुर लैंडफिल साइट का एक बड़ा हिस्सा नाले में गिर गया था, नाले का पानी सड़क पर आ गया था। दो कार व सात दो पहिया वाहन बहकर नदी में चले गए थे। इस हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। यह लैंडफिल के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था। हादसे के वक्त लैंडफिल की ऊंचाई 50 मीटर के आसपास थी, जो निर्धारित ऊंचाई से 30 मीटर अधिक थी। इसको लेकर काफी राजनीति भी हुई थी। 12 जून 2023: गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग। 120 अप्रैल 2022: एक माह में तीन बार गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग। 129 मार्च 2022: गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग को तीन दिन में बुझाया गया था। 1 अप्रैल 2021: गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग।

## मतदाता सूची में इस तरह शामिल कराएं अपना नाम, दिल्ली में सिर्फ दो सप्ताह का समय

परिवहन विशेष न्यूज

चुनाव आयोग दिल्ली के सातों संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। आयोग के निर्देश पर सभी क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस दौरान नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए भी अपील की जा रही है। अगले सप्ताह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली में चुनाव की सरगमी तेज हो जाएगी।

**नई दिल्ली।** चुनाव आयोग दिल्ली के सातों संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। आयोग के निर्देश पर सभी क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस दौरान नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए भी अपील की जा रही है। अगले सप्ताह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली में चुनाव की सरगमी तेज हो जाएगी। इसलिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए भी अब सिर्फ दो सप्ताह का ही समय शेष है। इसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**इस तरह कर सकते हैं आवेदन**



इसलिए लोग दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉग मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वोटर हेल्पलाइन मोबाइल या ईसीओ कार्यालय के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

**14 मई तक करें आवेदन**  
सीईओ कार्यालय के अनुसार, नामांकन की

अंतिम तिथि तक नए वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को चुनाव है। इसके लिए 29 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और छह मई नामांकन की अंतिम तिथि है। इसलिए नामांकन की अंतिम तिथि में 14 दिन बाकी है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के

लिए आवेदन देने के बाद उसके सत्यापन और मतदाता सूची में नाम शामिल करने में एक सप्ताह से दस दिन समय लगता है। दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र 22 जनवरी को तैयार हो गया था और उसका प्रकाशन भी हो चुका है।

**छह मई के बाद मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा नाम**

इसके बाद आवेदन देने वाले मतदाताओं को एक पूरक सूची तैयार होगी और उसका प्रकाशन भी होगा। इसलिए छह मई के बाद कोई नया

आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छह मई के बाद आवेदन देने वालों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा।

छह मई तक आवेदन देने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल होने के बाद वे आनलाइन ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि मतदाता पहचान पत्र घर नहीं पहुंच पाने की स्थिति में चुनाव वाले दिन मतदान के लिए ई-मतदाता पहचान पत्र इस्तेमाल किया जा सकता है।

## 'रोज इंसुलिन मांग रहा हूं..', तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल प्रशासन के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली सीएम का बयान आया है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर दावा किया कि तिहाड़ जेल के दोनों बखान झूठे हैं।

**नई दिल्ली।** आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने इस संबंध में तिहाड़ जेल अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा, रमैने अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा। मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बखान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में तीन बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर 250 से 320 के बीच जाती है।"

**अरविंद केजरीवाल ठीक हैं - तिहाड़ जेल प्रशासन**

इससे पहले शनिवार को इंसुलिन विवाद के बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ठीक हैं। साथ ही एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 40 मिनट तक परामर्श दिया, जिस दौरान उन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य चिंता नहीं होने का आश्वासन दिया गया और निर्धारित दवाएं लेना जारी रखने की सलाह दी गई।

## घर बैठे कमाई के चक्कर में शख्स ने बच्चों की पढ़ाई और शादी की रकम गंवाई



साइबर थाने में सेक्टर-22 में रहने वाले हेमंत ने दी शिकायत में बताया कि वह एक कारखाने में सिक्वोरिटी सुपरवाइजर है। चार मार्च को उसकी टेलीग्राम आईडी पर घर बैठे कमाई कराने का ऑफर आया। इसमें बताया गया कि एएमसी थियेटर कंपनी में कुछ पैसे लगातार काम किया जा सकता है। इसमें मोटा मुनाफा होगा। इसके बदले खूब कमीशन मिलेगा। उसने इस काम में रुचि दिखा दी।

अधिक कमीशन का दिया प्रलोभन इसके बाद पहले दिन उसे बिना पैसे लगाए उसका डमी अकाउंट बनाकर दे दिया गया। इसमें उसे 1150 रुपये प्राप्त हुए। उसने पैसे निकाल लिए। पांच मार्च को उससे 11 हजार रुपये जमा कराने को कहा गया। उसने यह पैसे जमा करा दिए। इसके बाद कहा गया कि यदि ज्यादा पैसे जमा करोगे तो अधिक कमीशन मिलेगा। इसके बाद उसने 22 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। पैसे जमा करने के बाद उसे टास्क देना शुरू कर दिया गया।

## अप्रैल में तपा रही जून सी गर्मी, पड़ रहे लू के थपेड़े

एनसीआर में बढ़ती गर्मी अप्रैल माह में जून की गर्मी का एहसास करा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को भी तेज धूप व गर्म हवा का सामना करना पड़ेगा। दो दिन गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

**परिवहन विशेष न्यूज**  
राजियाबाद। तेज धूप व लू के थपेड़ों के साथ बढ़ती गर्मी अप्रैल माह में जून की गर्मी का एहसास करा रही है। सुबह से ही तेज धूप में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। रविवार को हल्के बादल भी तेज धूप में बेअसर रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन ऐसे ही गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। इस साल अप्रैल माह में गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। सुबह से ही तेज धूप के साथ गर्म हवा चलने लगती है। जिससे गर्मी का एहसास ज्यादा होता है। दोपहर में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज रविवार को जो लोग काम से घर से बाहर निकलते हैं वह भी धूप व गर्म हवा से बचाव करते दिखे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम 13 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 24 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को



भी तेज धूप व गर्म हवा का सामना करना पड़ेगा। दो दिन गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और

## पंजाबी समाज के गढ़ में 26 अप्रैल को भाजपा करेगी विजय संकल्प रैली

परिवहन विशेष न्यूज

पंजाबी समाज के गढ़ में 26 अप्रैल को भाजपा विजय संकल्प रैली करेगी। शीतला मंडल में रैली को लेकर संपर्क करने की जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक नवीन गौयल को अर्जुन मंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता हरविंदर कोहली को दयानंद मंडल में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी को एवं सरस्वती मंडल में खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुकेश शर्मा पहलवान को सौंपी गई है।

गुरुग्राम पंजाबी समाज को साधने के लिए भाजपा गुडगांव विधानसभा क्षेत्र स्तर की रैली भीमनगर के रामलीला मैदान में 26 अप्रैल आयोजित करेगी। भीमनगर का इलाका पंजाबी समाज का गढ़ माना जाता है। मुख्य अतिथि पंजाबी समाज से आने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाया गया है।

बैठक पर तय की गई जिम्मेदारी भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेशस्तरीय नेताओं की एक-एक रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 26 अप्रैल को गुडगांव विधानसभा क्षेत्र की रैली तय की गई है। तैयारी को लेकर रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष कमल यादव ने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय गुरुकमल में बैठक कर जिम्मेदारी तय की।

शीतला मंडल में रैली को लेकर संपर्क करने की जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक नवीन गौयल को, अर्जुन मंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता हरविंदर कोहली को, दयानंद मंडल में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी को एवं सरस्वती मंडल में खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुकेश शर्मा पहलवान को सौंपी गई है।

रैली को लेकर संपर्क अधिधान के दौरान सभी नेता व कार्यकर्ता मोदी की गारंटी के बारे में चर्चा करेंगे। रैली में भी मोदी की गारंटी पर ही विशेष रूप से लोगों से संवाद किया



जाएगा। **बादशाहपुर व पटौदी विधानसभा में जल्द होगी रैली**

जिलाध्यक्ष कमल यादव का कहना है कि पार्टी जीत के लिए नहीं बल्कि भारी अंतर से

जीत के लिए काम कर रही है। सभी कार्यकर्ता दिन-रात इसके लिए लगे हुए हैं। बादशाहपुर एवं पटौदी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी रैली की घोषणा जल्द की जाएगी। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष

उषा प्रियदर्शी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गौयल, खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक मुकेश शर्मा पहलवान, पार्टी के जिला महामंत्री रामबीर भाटी, सर्वप्रिय त्यागी, उपाध्यक्ष सुंदरी खत्री, पूर्व पाषण्ड सीमा

पाहुजा, कार्यालय निर्माण विभाग संयोजक हरविंदर कोहली, कार्यालय सचिव यादराम जोया, जिला सह मीडिया प्रमुख पवन यादव, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मयंक निर्मल आदि शामिल हुए।

## शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने मां को पीटकर किया घायल, रिपोर्ट दर्ज

नोएडा कोतवाली जारचा क्षेत्र के एक गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने मां को जमीन पर गिराकर घायल किया। छाया गांव की रहने वाली महेंद्री का आरोप है कि शनिवार को बेटा सोनू शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इस पर भड़के बेटे सोनू ने जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।

**नोएडा।** रकोतवाली जारचा क्षेत्र के एक गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने मां को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से पीटकर घायल किया।

पुलिस के अनुसार छाया गांव में परिवार के साथ रहने वाली महेंद्री का आरोप है कि शनिवार को बेटा सोनू शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। मां उसके शराब पीने के कारण दुखी थी, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इस पर भड़के बेटे सोनू ने मां को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।

**पड़ोसियों के पहुंचने के बाद आरोपी फरार**  
चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों के मौके पर आने से मां को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।



पड़ोसियों ने महेंद्री को अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बाद मां ने बेटे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी

जारचा सुनील बैसला ने कहा कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

## चुनाव में गौतमबुद्ध नगर के मतदान केंद्रों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, निर्भीक होकर करें मतदान

परिवहन विशेष न्यूज

गौतमबुद्ध नगर में दिल्ली व हरियाणा राज्यों से लगने वाली सीमा पर कुल 26 बैरियर लगे हैं। सभी बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्थानीय थाना व चौकी से इसकी 24 घंटे निगरानी हो रही है। जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों ने कमर कस ली है।

**गाजियाबाद।** लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में चुनाव प्रचार की सरगमी बढ़ गई है। एक ओर प्रत्याशी चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को पुलिस अधिकारियों ने कमर कस ली है। जिले में पहली बार बहुमंजिला सोसायटियों के परिसर में मतदान केंद्र बने हैं।

निष्पक्ष, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने, संवेदनशील बूथों समेत सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और मतदान के दौरान की गई तैयारियों आदि को लेकर दैनिक जागरण के संवाददाता गौरव भाद्रज ने गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से बात की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश...

**जिले में संगठित अपराध की कमर टूट चुकी है, पर माफिया के मुगं मतदान को प्रभावित न कर सकें, इसकी क्या तैयारी की गई है ?**

चुनाव की घोषणा से ही माफिया गिरोह के सक्रिय सदस्यों पर नकेल कसने की कवायद जारी है। इनकी 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। 1750 से अधिक गुंडाएक्ट के तहत जिला बंदर हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी, जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई जारी है।

जिले में पांच अलग-अलग माफिया गिरोह हैं। उनके सक्रिय सदस्यों पर नजर है। इनमें बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। कोशिश है कि चुनाव के दौरान एक भी माफिया चुनाव के दौरान खलल डालने के लिए जिले में मौजूद नहीं होगा।

**जिले में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस की क्या तैयारी है ?**

जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक तैयारी है। जिले को सात सुपर जोन व 120 सेक्टरों में बांटा है। हर सुपर जोन की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अधिकारियों को दी

है। सेक्टर मजिस्ट्रेट का निम्ना पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। हमारी कोशिश है कि किसी भी सूचना पर पांच मिनट में पुलिस पहुंचे व शांतिपूर्ण समस्या का समाधान हो। बाहर से फोर्स मिल चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर बाहर से आर्बिट्रल फोर्स तैनात होगा। जिले का फोर्स ही कानून व्यवस्था देखेगा।

**जिले की सीमा दो राज्यों दिल्ली व हरियाणा के अलावा तीन जिले बुलंदशहर, गाजियाबाद व हापुड़ से मिलती है। चुनाव के दौरान नाकेबंदी की क्या तैयारी है ?**

जिले की दिल्ली व हरियाणा राज्यों से लगने वाली सीमा पर कुल 26 बैरियर लगे हैं। सभी बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्थानीय थाना व चौकी से इसकी 24 घंटे निगरानी हो रही है।

वहीं बुलंदशहर, गाजियाबाद व हापुड़ जिले के साथ की सीमा पर 24 स्थान पर नाकेबंदी है। इनसे मतदाताओं को बिना किसी परेशानी के मतदान कराएंगे।

**पुलिस पर प्रश्न: आरोप लगते हैं कि वह सत्ताधारी दल के प्रत्याशी की मदद करती है। इससे बचाव की क्या योजना है ?**

ऐसा किल्कुल नहीं है। पुलिस निष्पक्ष काम करती है। पुलिसकर्मियों की तीन राउंड की ब्रीफिंग हो गई है। चुनाव ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी, नाका ड्यूटी, क्लस्टर ड्यूटी, एफएस्टी, एएसटी सभी को अलग-अलग दिशा-निर्देश दिए हैं। चुनाव को पारदर्शिता से कराना व जनता को पारदर्शिता दिखे, दोनों अहम हैं।

अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है। आगे भी आरोप न लगे, इसके लिए पुलिस का राज्य स्तर का रैंडमाइजेशन किया गया है। हर मतदान केंद्र पर बाहर का फोर्स तैनात रहेगा। जिले में पिछले तीन वर्षों से तैनात पुलिसकर्मियों का जनवरी में ही ट्रांसफर हो गया है।

**चुनावों में प्रायः पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठते हैं। मतदाता कहते हैं कि वह बूध पर मतदान के लिए जाते हैं तो पुलिस ठीक से व्यवहार नहीं करती। व्यवहार में सुधार के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं ?**

मतदाताओं से ही नहीं, आमजन से भी मधुर व्यवहार रखने के निर्देश वक्त-वक्त पर पुलिसकर्मियों को दिए जाते हैं। जिले में काफी मतदाता सेक्टर व सोसायटियों में रहते हैं। जिले के पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वह मतदाताओं से शालीनता से बात करें।

## मतदाता की बेरुखी लोकतंत्र के लिए नहीं हैं अच्छे संकेत

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले मतदाताओं को किसी भी हालत में देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं कहा जा सकता। आज चुनाव आयोग ने जहां अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागृत किया है वहीं पारदर्शी और सहज मतदान व्यवस्था सुनिश्चित की है।

18 वीं लोकसभा के लिए पहले चरण की 102 सीटों के लिए मतदान के प्रति मतदाताओं की उदासीनता ने निराशा ही किया है। आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी मतदान प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर कम होना निश्चित रूप से किसी भी रूप में लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। चुनाव आयोग के लाख प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत कम होना निश्चित रूप से सोचने को मजबूर कर देता है। चुनाव आयोग से पहले चरण के मतदान के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो साफ हो जाता है कि 2019 की तुलना में दो प्रतिशत तक मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। हालांकि त्रिपुरा और सिक्किम में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत को छूने में सफल रहा है पर वहां भी 2019 की तुलना में कम है। त्रिपुरा में 2019 के 81.9 प्रतिशत की तुलना में 81.5 प्रतिशत और सिक्किम में 84.8 प्रतिशत की तुलना में 80 प्रतिशत मतदान रहा है। पहले चरण के चुनावों में मतदान का सबसे कम प्रतिशत बिहार का रहा है जहां मतदान का

आंकड़ा 50 प्रतिशत को भी छू नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ में अवश्य 2019 की तुलना में एक प्रतिशत से कुछ अधिक मतदान रहा है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है 12 सीटों पर हुए मतदान में मतदान प्रतिशत में 6 फीसदी की गिरावट रही है। सभी सीटों पर मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में कम रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ें आंशिक सूचना के आधार पर हैं पर इनमें कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। मजे की बात यह है कि पहले चरण में लोकसभा की 543 सीटों में से 20 प्रतिशत से कुछ कम 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। यदि मतदाताओं का अगले चार चरणों के मतदान में भी यही रुख रहता है तो यह चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गैरसरकारी संगठनों सहित सभी के लिए चिंतनीय हो जाता है।

मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले मतदाताओं को किसी भी हालत में देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं कहा जा सकता। आज चुनाव आयोग ने जहां अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागृत किया है वहीं पारदर्शी और सहज मतदान व्यवस्था सुनिश्चित की है। आज मतदाताओं को किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक मतदान केंद्र पर एक सीमा तक ही मतदाता होने के साथ ही मतदान



केंद्र पर सभी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अब तो मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता क्रमांक से लेकर मतदान केंद्र तक की जानकारी का समावेश करते हुए परची उपलब्ध कराई जाती है। सीनियर सिटिजन और मतदान केंद्र तक जाने में अक्षम मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। मतदाताओं को जागृत करने के लिए प्रचार के सभी माध्यम यहां तक कि सोशियल मीडिया का उपयोग किया जाने लगा है। मतदान को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए संपूर्ण व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। यहां तक कि उम्मीदवार से संबंधित जानकारी साझा की जाती है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था होती है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान केंद्र पर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि साक्षरता और लोगों में जागरूकता आई है। चुनाव आयोग के अलग अलग ऑब्जरवर द्वारा पूरी व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाती है ताकि राजनीतिक दलों या

मतदान प्रतिशत 90 के आंकड़े को भी नहीं छूता है तो यह थोड़ा निराशाजनक है। हालांकि आजादी के बाद सर्वाधिक मतदान 1984 के 64.01 के आंकड़ों को 2014 में पीछे छोड़ा गया पर 2019 के पहले चरण के मतदान से निराशा ही हाथ लगी है। आखिर शिक्षित मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के प्रति इतना गैरजिम्मेदार कैसे हो रहा है। सब कुछ को अलग कर दिया जाये तो भी इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि देश के नागरिक का भी अपने देश के प्रति लोकतंत्र के प्रति दायित्व होता है। आखिर हम सरकार की

आलोचना करने में तो पीछे नहीं रहते पर कभी हमने सोचा है क्या कि हम मताधिकार का उपयोग करने के अपने दायित्व को नहीं समझ पाते हैं। अपनी सरकार चुनने के अवसर पर हम हमारे दायित्व को कैसे भूल जाते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी अपने आप में गंभीर हो जाती है। भारत जैसे देश के आम नागरिकों द्वारा इस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाना किसी अपराध से कम नहीं माना जाना चाहिए। हमें गर्व होता है कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर हमें उस समय नीचे देखने को भी मजबूर होना पड़ता है जब इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व पर आमनागरिक अपने दायित्व को समझने और उसे पूरा करने की भूल कर बैठता है और मताधिकार का उपयोग नहीं कर व्यवस्था को ठेंगा बनाने का प्रयास करते हैं। मेरा तो यहां तक मानना है कि नोटा का प्रयोग भी सही विकल्प नहीं है वहीं मतदान का बहिष्कार तो देशद्रोह से कम अपराध नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार गैरसरकारी संगठनों और समाज के प्रबुद्ध जनों को सोचना होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी आहुति देने के काम से मुंह मोड़ने वालों के प्रति कोई सख्त कदम जैसा प्रावधान होना ही चाहिए। कोई ना कोई ऐसा संदेश जाना चाहिए ताकि लोग मतदान के प्रति संवेदनशील हो और मतदान अवश्य करें। यह समूची व्यवस्था को ही सोचने को मजबूर कर देता है। आने वाले चार चरणों में होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदाता हिस्सा ले इसके लिए सभी स्तर पर समन्वित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

## टायरो में क्यों भरवाए नाइट्रोजन, जाने

परिवहन विशेष न्यूज

टायर रखरखाव युक्तियाँ: लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या उन्हें अपनी कार/बाइक के लिए नाइट्रोजन हवा का उपयोग करना चाहिए। कुछ साल पहले तक वाहनों में सामान्य हवा भरने का चलन था, लेकिन अब लगभग हर जगह टायर की दुकानों में नाइट्रोजन फिलिंग स्टेशन शुरू कर दिए हैं, यह दावा करते हुए कि यह पुरानी सामान्य हवा की तुलना में टायरों के लिए बेहतर है। लेकिन, क्या ये दावे सच हैं? क्या नाइट्रोजन वास्तव में नियमित हवा से अधिक प्रीमियम है और टायर जीवन के लिए बेहतर है? नाइट्रोजन क्यों? सबसे पहला और महत्वपूर्ण दावा है नाइट्रोजन लंबे समय तक दबाव बनाए रखती है और यह सच भी है। नाइट्रोजन के अणु बड़े होते हैं और सामान्य हवा की तुलना में धीमी गति से चलते हैं और इसलिए, सामान्य हवा के विपरीत, नाइट्रोजन आपके टायरों से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलेगी। नाइट्रोजन ठंडी रहती है और वायुमंडलीय हवा की तरह तापमान परिवर्तन के कारण फैलती या सिकुड़ती नहीं है। इस कारण से नाइट्रोजन का उपयोग विमान के टायरों को भरने और मोटरस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन सीमेंट सड़कों पर तेज गति पर अचानक टायर फटने की घटना को भी कम कर सकती है। संपीड़ित हवा में नमी होती है जो टायर के जीवन के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि यह समय के साथ टायर की संरचना को खराब कर देती है, लेकिन यह सामान्य

कारों पर लागू नहीं होता है जो अक्सर उपयोग की जाती हैं और शायद ही कभी प्रभावित होती हैं। सामान्य हवा क्यों? आप अपने वाहन के टायरों में सामान्य हवा भरने में गलती नहीं कर सकते इसे प्राप्त करना आसान है, कुछ हद तक सस्ता है, यह टायरों के आविष्कार के बाद से ही मौजूद है और वर्षों से इसकी उपयोगिता साबित हुई है। वास्तव में क्या मायने रखती है? नाइट्रोजन या मानक वायु विकल्प के बावजूद कार निर्माता द्वारा अनुशंसित सही टायर दबाव अधिक महत्वपूर्ण है। कम या अधिक मुद्रास्फीति कई समस्याओं का कारण बन सकती है, जिसमें अत्यधिक घिसाव से लेकर खराब पकड़ और इंधन की खपत और वाहन प्रदर्शन तक शामिल हैं। नाइट्रोजन और सामान्य हवा के बीच भ्रम आपके उपयोग के मामले और नाइट्रोजन स्टेशन की उपलब्धता पर निर्भर करता है, लेकिन उचित टायर दबाव बनाए रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। क्या नाइट्रोजन और सामान्य हवा को मिलाना सुरक्षित है? नाइट्रोजन को सामान्य हवा में मिलाना कोई समस्या नहीं है, हालांकि नाइट्रोजन को सामान्य हवा में मिलाने से इसके लाभ कम हो जाएंगे। वास्तव में नियमित संपीड़ित हवा में 78% नाइट्रोजन और लगभग 20% ऑक्सीजन होती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संपीड़ित हवा और नाइट्रोजन को मिलाने से कोई जोखिम या रासायनिक समस्या नहीं होती है। अगर टायरो में हवा कम लग रही है और यात्रा के दौरान आपको नाइट्रोजन न मिले तो नियमित रूप से हवा भरने से न कतराएँ।



## टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक, डिजाइन से उठा पर्दा, जानिए बैटरी पैक से लेकर रेंज तक सबकुछ

Mahindra XUV.e9 का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। महिंद्रा की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग भी शुरू हो गयी है। टेस्टिंग के दौरान महिंद्रा की अपकमिंग कार की झलक देखने को मिली है। इस दौरान इस कार का फ्रंट और साइड प्रोफाइल का डिजाइन सामने आया है। महिंद्रा की यह अपकमिंग ईवी XUV 700 पर आधारित होगी जो अप्रैल 2025 में पेश की जा सकती है।

नई दिल्ली। महिंद्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने की तैयारी में है। Mahindra XUV.e9 का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी की कथित अपकमिंग ईवी डॉट ई9 को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, जिससे उसके डिजाइन को लेकर जानकारी पता चली है। Mahindra XUV.e9 को लेकर बताया जा रहा है कि यह XUV 700 SUV का ईवी अवतार है।

**Mahindra XUV.e9: डिजाइन**  
टेस्टिंग के दौरान देखी गई महिंद्रा की इस ईवी का डिजाइन पिछले साल दिखाए कॉन्सेप्ट की तरह ही है। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो इसमें स्प्लिट हेडलैंप, फुल-विथ एलईडी लाइट बार और क्लोज ऑफ़िशिल दिया गया है। वहीं साइड प्रोफाइल में कंपनी ने लेटेस्ट अलॉय व्हील्स दिए हैं, जो BE.09 से इन्स्प्रायर्ड हैं।

महिंद्रा की यह अपकमिंग कार coupe-SUV होगी, जिसमें कनेक्टेड LED टेल-लैंप दिए जाएंगे। रियर बंपर में रजिस्ट्रेशन प्लेट की जगह दी गई है। इसके साथ ही रियर गेट में महिंद्रा का लोगो दिया गया है। संभव है कि लोगो के ठीक नीचे नेमप्लेट दी जाए।

**Mahindra XUV.e9: इंटीरियर**  
अपकमिंग XUV.e9 के कथित स्पॉट



शॉट में दावा किया गया है कि इसमें 12.3-इंच की तीन-डिस्प्ले मिलेगी। इसके साथ ही 2-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसके साथ ही सेंटर कॉन्सोल में कॉन्वेनशनल शिफ्ट लीवर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर के साथ आएगी।

**Mahindra XUV.e9: रेंज और बैटरी**  
महिंद्रा की XUV.e9 को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें XUV.e8 वाला बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है, जो भारत में अगले साल लॉन्च होनी है। इस कार में 80kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसमें अल-व्हील ड्राइव के लिए दो मोटर का स्पॉट दिया जाएगा। यह मोटर 230hp से 350hp की पावर जनरेट करेगी। कार की संभावित रेंज 435-450km है।

**Mahindra XUV.e9 कब होगी लॉन्च?**  
महिंद्रा की अपकमिंग ईवी XUV.e9 को लेकर बताया जा रहा है कि यह अप्रैल 2025 में लॉन्च की जा सकती है।

### प्रीमियम ऑडियो सिस्टम के साथ आएगी महिंद्रा XUV 3X0, पांचवें टीजर में मिली जानकारी

नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता Mahindra की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही नई एसयूवी (Mahindra XUV 3X0) को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी ने हाल में ही सोशल मीडिया पर पांचवां टीजर जारी किया है। जिसमें नई एसयूवी XUV 3X0 के एक और फीचर की जानकारी मिल रही है। कंपनी नई एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को देने की तैयारी कर रही है।

**Mahindra XUV 3X0 का पांचवां Teaser जारी**  
महिंद्रा की ओर से सोशल मीडिया पर नई एसयूवी XUV 3X0 का पांचवां टीजर जारी किया गया है। कंपनी ने 20 सेकेंड का तीसरा वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। जिसमें एसयूवी में मिलने वाले ऑडियो सिस्टम की जानकारी मिल रही है।

**मिली यह जानकारी**  
नए टीजर में कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि Mahindra XUV 3X0 में Harman Kardon के सात स्पीकर वाले ऑडियो सिस्टम को दिया जाएगा। कंपनी की ओर से टीजर में यह भी बताया गया है कि इस प्रीमियम ऑडियो सिस्टम को एसयूवी के कुछ ही वैरिएंट में ऑफर किया जाएगा।

**पहले मिली थी यह जानकारी**  
कंपनी की ओर से एसयूवी के लॉन्च से पहले लगातार टीजर जारी किए जा रहे हैं। जिनमें एसयूवी से जुड़ी कई जानकारियों को बताया जा चुका है। कंपनी की ओर से अभी तक जारी किए टीजर में कई फीचर्स की जानकारी दी जा चुकी है।



## भरी गर्मी में ड्राइविंग को रखना चाहते हैं कूल तो करें यह जरूरी काम, बीच रास्ते में नहीं रुकेगी गाड़ी



समूचे भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। जिस तरह हम गर्मियों के महीनों में अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए तैयारियां करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी कार को भी कुछ उपचार और बचाव की जरूरत होती है। आइए, उन 5 जरूरी कामों के बारे में जान लेते हैं, जिनकी मदद से आप भरी गर्मी में कूल ड्राइविंग कर सकेंगे।

**AC की सर्विस गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा काम करने वाले कंपोनेंट्स में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नाम शामिल है।** कार मालिक अक्सर अपने एसी यूनिट के बारे में शिकायत करते हुए कहते हैं कि गर्मी के दौरान केबिन को ठंडा करने में बहुत समय लगता है। इस समस्या के बचने के लिए सुनिश्चित करें कि केबिन एयर फिल्टर साफ है, क्योंकि गर्मियों के परिणामस्वरूप एसी का प्रदर्शन

खराब हो सकता है और केबिन के अंदर दुर्गंध भी आ सकती है। **विंडशील्ड वाइपर की जांच** विंडशील्ड वाइपर बरसात के मौसम में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। गर्मियों के दौरान इन पर सीधी गर्मी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप रबर सूख जाती है। इस वजह से वाइपर विंडशील्ड को साफ करने में कम प्रभावी हो जाते हैं। वाइपर ब्लेड्स की टूट-फूट की जांच करना सुनिश्चित करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदल दें।

**पलुड चेक-अप उच्च** तापमान के परिणामस्वरूप अक्सर इंजन ऑयल जल्दी जल जाता है, खासकर यदि तेल पुराना और खराब हो चुका हो। इंजन ऑयल लेवल की नियमित रूप से जांच करना और पावरप्लॉट को किसी भी नुकसान से बचने के लिए ऑईएम द्वारा अनुशंसित उचित तेल जोड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंजन ऑयल लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है

और मोटर के चलने वाले हिस्सों को घर्षण से बचाता है।

**बैटरी की जांच** कार की बैटरी को सर्वोत्तम स्थिति में रखने का सबसे अच्छा तरीका इसे साफ रखना है। यह बैटरी केबलों को नियमित रूप से अलग करके और टर्मिनलों को पोंछकर किया जा सकता है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि बैटरी सुरक्षित रूप से बंधी हुई है और सभी कनेक्शन ठीक से सुरक्षित हैं। यह जांचना सुनिश्चित करें कि बैटरी टर्मिनल जंग और गंदगी-मुक्त हैं।

**टायर प्रेशर की चेकिंग** बाहरी तापमान के आधार पर टायरों में प्रतिदिन एयर प्रेशर घटता और बढ़ता रहता है। गर्म मौसम टायर के वायु दबाव को बढ़ाकर प्रभावित करता है, जबकि कम फुलाए गए टायरों के परिणामस्वरूप कार की फ्यूल एफिशियेंसी घट जाती है। इस समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से टायर प्रेशर चेक करते रहें।

## वोक्सवैगन ताइगुन जीटी लाइन और जीटी प्लस स्पोर्ट हुई लॉन्च

दुनिया की प्रमुख कार निर्माताओं में शामिल फॉक्सवैगन की ओर से भारतीय बाजार में कई दमदार एसयूवी और सेडान कारों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से Taigun GT Line और GT Plus Sport को लॉन्च कर दिया गया है। इन एसयूवी में किस तरह की खूबियों को दिया गया है और इनकी क्या कीमत तय की गई है।



नई दिल्ली। दमदार कारों और फीचर्स के लिए पहचान रखने वाली Volkswagen ने भारतीय बाजार में दो बेहतरीन एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की ओर से Volkswagen Taigun GT Line और GT Plus Sport को लॉन्च किया गया है। हम इस खबर में इनकी खूबियों और कीमत की जानकारी दे रहे हैं।

**लॉन्च हुई Volkswagen Taigun GT Line और GT Plus Sport**  
फॉक्सवैगन की ओर से भारतीय बाजार में Volkswagen Taigun GT Line और GT Plus Sport को लॉन्च कर दिया गया है। सामान्य वर्जन के मुकाबले इनमें कंपनी ने कई बेहतरीन फीचर्स और इंजन को दिया है।

कैसी हैं खूबियां

Volkswagen Taigun GT Line में कंपनी की ओर से स्पॉर्टी ब्लैक थीम को दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स, डार्क एलईडी हेडलैंप, डीआरएल, 25.65 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, छह एयरबैग को दिया गया है। वहीं GT Plus Sport स्पोर्ट्स हेडलैंप, कार्बन स्टील ग्रे रूफ, ग्रिल, फेंडर और रियर प्रोफाइल पर रेड जीटी ब्रांडिंग, डार्क क्रोम डोर हैंडल और फ्रंट एक्सल पर रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। ये ग्रिल, डिफ्यूजर, ट्रैपेजॉइडल विंग, नए 17 इंच के अलॉय व्हील और फेंडर बैज जैसे कई एलीमेंट को ब्लैक-आउट फिनिश के साथ दिया जा रहा है।

**कितना दमदार इंजन**  
फॉक्सवैगन ताइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में 1.5 लीटर टीएसआई इंजन दिया गया है। जिसके साथ छह स्पीड मैनुअल और सात

स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। ताइगुन जीटी लाइन में कंपनी ने एक लीटर का टर्बोचार्ज टीएसआई इंजन दिया है। इसके साथ छह स्पीड मैनुअल और छह स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है।

**कितनी है कीमत**  
कंपनी की ओर से ताइगुन जीटी लाइन के मैनुअल ट्रांसमिशन वैरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 14.08 लाख रुपये है। इसके ऑटोमैटिक वैरिएंट की 15.63 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं ताइगुन के जीटी प्लस स्पोर्ट वैरिएंट की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत 18.54 लाख रुपये है। इसके डीएसजी टॉप वैरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 19.74 लाख रुपये तक की गई है।

## टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया लीडर एडिशन हुआ लॉन्च, कैसी हैं खूबियां

नई दिल्ली। फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में Toyota Fortuner को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कंपनी की ओर से इस एसयूवी का नया Leader Edition भारत में लॉन्च किया गया है। एसयूवी के नए एडिशन में किस तरह की खूबियों को दिया जा रहा है।



**Toyota Fortuner का Leader Edition हुआ लॉन्च**  
टोयोटा की ओर से फॉर्च्यूनर एसयूवी का Leader एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इस एडिशन में कुछ खास बदलाव किए हैं। जिनको एक्सटीरियर और इंटीरियर में देखा जा सकता है।

**क्या हैं खूबियां**  
फॉर्च्यूनर के नए एडिशन में कंपनी की ओर से फ्रंट और रियर स्पॉयलर दिए गए हैं। इसके साथ ही Leader Edition में काले रंग के अलॉय व्हील्स, टीपीएमएस, ड्यूल टोन पेंट स्कीम को दिया जा रहा है। इंटीरियर में भी ड्यूल टोन सीट को भी दिया गया है। नए एडिशन के साथ फॉर्च्यूनर में वायरलेस चार्जर, ऑटो फोर्लडिंगमिरर को भी दिया गया है।

**कंपनी के अधिकारियों ने कही यह बात**  
टोयोटा किलोसकार के वीपी सबरी मनोहर ने कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे ग्राहक होते हैं। बेहतरीन सुविधाओं और ड्राइविंग अनुभवों के लिए उनकी बढ़ती प्रार्थनाएं और इच्छाएं हमारी निरंतर खोज को प्रेरित करती हैं। फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन को पावर और स्टाइल की एक अद्वितीय भावना प्रदान करते हुए, ज्यादा एड-ऑन सुविधाओं के साथ अपने बोलड स्टाइल स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन अपने सेगमेंट में सर्वोत्तम पेशकश देने, पावर और स्टाइल के साथ आगे बढ़ने में टोयोटा की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

हम भारत में फॉर्च्यूनर के उत्साही प्रशंसकों के हमारे ब्रांड में विश्वास के लिए उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम एसयूवी के शौकीनों को फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन के साथ उत्साहित करना जारी रखेंगे, जो बोलड एक्सटीरियर डिजाइन, आकर्षक और आरामदायक इंटीरियर और 'लीड इन पावर' के लिए उन्नत हाई-टेक फीचर्स की पेशकश करेगा।

# ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़ने का परिदृश्य



डा. जयंती लाल भंडारी

**यह अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था नए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुआयामी उपयोगिता देते हुए दिखाई देगी। हम उम्मीद करें कि लोकसभा चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी...**

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने से निजी खपत में भी तेजी आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और प्रमुख मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि अनुकूल मानसूनी मौसम के कारण इस वर्ष 2024 में भारत में अच्छी वर्षा के स्पष्ट संकेत खेती और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा कहा गया है कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद है जिससे कृषि गतिविधियों में और तेजी आएगी। ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी। गौरतलब है कि विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। गांवों में न केवल कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, वरन् गांवों में फ्रिज, दोपहिया वाहन और टीवी की खरीददारी में सबसे उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पिछले एक दशक में शहरी परिवारों के मुकाबले ग्रामीण परिवारों का खर्च तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय, ग्रामीणों के रोजगार की मनरेगा योजना तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति और मांग में भारी इजाफा हुआ है। इससे ग्रामीण भारत की आर्थिक ताकत में इजाफा हुआ है। यद्यपि अभी आम चुनाव के बाद जून 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के मूर्तरूप लेने में कोई दो माह बकाया है, लेकिन उच्च प्रशासनिक स्तर पर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मकसद से जिन क्षेत्रों के लिए आगामी पांच सालों के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाना शुरू की गई है, उनमें कृषि भी प्रमुख है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस समय पूरी दुनिया में भारत को खाद्यान्न का नया वैश्विक कटोरा माना जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। गेहूँ



तथा फलों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर तथा सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर भारत केला, आम, अमरूद, पपीता, अदरक, भिंडी, चावल, चाय, गन्ना, काजू, नारियल, इलायची और काली मिर्च आदि के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में कृषि एवं ग्रामीण विकास का नया आधार तैयार हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 15 फीसदी है।

सरकार के द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए एक के बाद एक रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। कृषि बजट में 10 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। किसानों के सशक्तिकरण, फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा 11 करोड़ से अधिक किसानों के जनधन खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 3 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित होने जैसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, कृषि, रसायन, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण, जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुओं के अधिक उपयोग से किसानों को लाभ हुआ है और इन सबसे जहां एक ओर भारत में कृषि क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी एवं लाभदायक बन रहा है, वहीं दूसरी ओर छोटे किसान अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। जहां कोविड-19 की आपदाओं से लेकर अनजान तक भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया के जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम

भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं भारत ने दुनियाभर में कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का अवसर भी मुठियों में लिया है। भारत से कृषि निर्यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत से अनाज, गैर-बासमती चावल, बाजरा, मक्का और अन्य मोटे अनाज के अलावा फलों एवं सब्जियों के निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई है। भारत के कृषि उत्पादों के बड़े बाजारों में अमरीका, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया शामिल हैं। कई छोटे देशों के बाजार भी मुठियों में आए हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बाजार में भारत के मसालों की खुशबू की धमक बहुत अधिक बढ़ी है। चूंकि देश में मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, अतएव इसका अंतर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग बढ़ने के रूप में रेखांकित हो रहा है। इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब करीब 50 हजार डॉलर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है।

खाद्य प्रसंस्करण में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। इस समय भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख टन से बढ़कर दो सौ लाख टन हो गई है। पिछले नौ वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण निर्यातों में 15 गुना वृद्धि हुई है। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के तहत पांच क्षेत्र हैं। एक डेयरी क्षेत्र, दो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, तीन अनाज का प्रसंस्करण, चार मांस मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण तथा पांच, उपभोक्ता वस्तुएं पैकेट बंद खाद्य और पेय

पदार्थ। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के यह भी उल्लेखनीय है कि इन प्रमुख पांच क्षेत्रों की व्यापक संभावनाओं को मुठियों में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे ग्रामीण भारत लाभान्वित हो रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2024 में भारत के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबुधाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के स्थायी समाधान के लिए जिस तरह

प्रभावी पहल की, उसके कारण इस सम्मेलन में इन मुठों पर कई विकसित देश भारत के किसानों के हितों के प्रतिकूल कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पाए।

ऐसे में अब भी भारत अपने किसानों के उपयुक्त लाभ के लिए नीतियां बनाते हुए खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक भंडारण की सुविधा से कृषि और ग्रामीण विकास के अभियान को आगे बढ़ा सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2024 को सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की जिस सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए प्रायोगिक परियोजना के तहत जिन 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को लक्षित किया गया है, उनके माध्यम से पैक्स की किसानों के हित में बहुआयामी भूमिका होगी। ऐसे में नई खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फिलहाल 1450 लाख टन की है, उसे आगे 5 साल में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था नए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुआयामी उपयोगिता देते हुए दिखाई देगी। हम उम्मीद करें कि लोकसभा चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी और इससे किसानों व ग्रामीण भारत के चेहरे पर मुस्कंराहट बढाते हुए दिखाई दे सकेगी। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि में व्यापक विकास के आसार हैं।

## संपादक की कलम से

### पालमपुर शहर की चीखें

नंगे दराट पर खून की धार जिस सार्वजनिक स्थान पर फूटी, वहां समाज, संस्कृति, शासन-प्रशासन और कानून व्यवस्था की नंगई सामने आ गई। पालमपुर शहर की चीखें उस वक्त शिमला तक जरूर पहुंची होंगी, जब असाध्य बेटी एक दरिंदे के सामने जान बचाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश तो धीरा के गांव में उस औरत ने भी की होगी, जिसकी एक दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी थी। हैरानी यह कि पालमपुर बस स्टैंड जैसी व्यस्त जगह में भी अपराध की टोह में एक बेटी पर घातक प्रहार इसलिए हो गए, क्योंकि कानून व्यवस्था कानों में रुई और आंखों पर काली पट्टी बांध कर अमान-चैन की सूचना देने में मशगूल है। इसी पालमपुर के व्यवसायी ने पुलिस महकमे के शिखर से हर स्रोत तक की शिकायत जब की थी, तो यह एक बुरा अनुभव मान कर औपचारिक कार्रवाई बन गई। मामला डीजीपी और एसपी की ट्रांसफरों तक सिमट कर अदालती हो गया, जबकि अंधी आंखों को भी ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था की तासीर में अब खोप उभर रहा है या अब दर्रा बदलना पड़ेगा। अपराध निरंकुश व बहुरूपिया बन कर खतरें बढ़ा रहा है, लेकिन हम राजनीतिक राजाओं और आकाओं की खिदमत में भूल गए कि कानून की असली चुनौतियां हैं कहां। कहीं कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व विधायकों के केंद्रीय सुरक्षा बलों के पहरे मिल रहे हैं, तो कहीं सरकार के ओहदेदारों की प्रदेश पुलिस हिफाजत में लगी है।

होती होगी पुलिस अलर्ट जब सत्ता के काफिलों में कर्तवियों की रक्षा की जाती है या सारा अमला जब बैठके करता होगा, तो कानून के हर पहलू को जगाया जाता होगा, वरना टोटे-टोटे लार्श और सूटा-सूटा नशा हमारे परिवेश में खतरों की घंटियां बजा रहा है। राजधानी शिमला तक चिट्ठी के सप्टाइड अगर कूरियर से तो नहीं है, तो इस नेटवर्क की किलेबंदी में न जाने कितने कसूरवार हैं और तब हम अपनी

युवा पीढ़ी को बचाएंगे कैसे। यकीनन दरिंदे के हाथों से कुछ दिलेर लोगों ने बेटी बचा ली, वरना कोसने के सिवा क्या मिलता। आश्चर्य है कि कुछ वर्ष पूर्व गुंडाया कांड की सलाखों में दबं और अपमानित कानून व्यवस्था ने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया कि अपराध बार-बार इस तरह गले पड़ रहा होता। कानून व्यवस्था के वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पक्ष को आज के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से लेना होगा। शहरी, ग्रामीण व हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों की कानून व्यवस्था के परेशान करने की दृष्टि से पुलिस बंदोबस्त की नई व्यवस्था जरूरी है। प्रदेश के कुछ जिलों व शहरों की कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस आयुक्तालयों की स्थापना के साथ ग्रामीण, ट्रैफिक, पर्यटन व सीमांत क्षेत्रों के लिए अलग से इंतजाम करने पड़ेंगे।

शहरी, ट्रैफिक व पर्यटन पैट्रोलिंग के लिए सख्त निर्देश व आवश्यक नियुक्तियां जरूरी हैं। पालमपुर के दराट कोप में अगर बिटिया चीख रही थी, तो उसकी चीखें पुलिस व्यवस्था तक क्यों नहीं पहुंची। हम भाईचारे में कानून-व्यवस्था को कब तक चलाएंगे। शहरों में बाइपास होते हुए भी अगर ट्रैफिक पुलिस का नियंत्रण सही से निर्देशित नहीं करता तो इतका शायद ही कोई समाधान होगा। ट्रैफिक के बीच युवा बाइकर जिस तरह परिवहन को असुरक्षित बना रहे हैं, वहां पुलिस महकमे का एक्शन है कहां। पीटान, समाज और सडक की भीड़ अगर अनियंत्रित छोड़ दी जाए, तो कानून के हाथ-पांव काटने के लिए कोई न कोई दराट चला जाएगा। पालमपुर के घटनाक्रम से कानून-व्यवस्था, समाज और पुलिस प्रशासन को अनेक सबक मिल रहे हैं। ऐसे में पालमपुर में पीडित बेटी को बचाती हुई जो लडकी बहादुरी से कर्म की नहीं परिभाषा लिख पाई, उसके लिए अभिभावकों को सलाम।

## ज्ञान

### शव संवाद-40

गोल-गप्पा जबसे खुद को पुरुष मानने लगा है, उसका जीवन औरत के मुंह में फंस गया है। हर वक्त फूला फूला सा रहता है। ढेर सारा खाता है, फिर भी उदास रहता है। इसे निगलने को हर कोई तैयार रहता है। बुद्धिजीवी ने हर बार अपने हालात को गोल गप्पे के करीब पाया। जब भी कोई संकेता है या गर्माहट के आंचल में उबालता है, यह फूल जाता है। बुद्धिजीवी कब नहीं फूला और कब फूला नहीं समाया। हर बार सरकार के परिवर्तन पर फूला फूला सा रहा। सच मानो यह तो ईंदिरा की इमरजेंसी की घोषणा पर भी फूला था, लेकिन फिर इसके अंग, ढंग और रंग जिस तरह फुलाए गए, इसके सामने अपने खोटा आ गए। हद यह कि इसने इमरजेंसी का पीछा नहीं छोड़ा। हटती तो भी खुशियां मनाई। इसके पास खुशियां मनाने के कई रिकार्ड हैं। स्वच्छता रैली के बाद या तो गोल गप्पा फूला या बुद्धिजीवी। वैसे स्वच्छता का संदेश गोल गप्पे से ज्यादा कौन देगा। किसी भी रेहड़ी पर जाइए तो देखेंगे कि भारतीय जनमानस गोल गप्पे पर जितना विश्वास करता है, उतना अपनी सरकार पर भी नहीं करता। गोल गप्पा बनाने व खिलाने वाले के हाथ पर तो इतना विश्वास है जितना चुनाव के बांड जारी करने वाले पर भी नहीं। न हम गोल गप्पे का कद देखते और न ही बेचने वाले के हाथ। जिस तरह इलेक्ट्रोल बांड पुलिंग है, उसी तरह गोल गप्पा भी पूरी तरह पुरुष, लेकिन इन दोनों का उपयोग खीलिंग ज्यादा करता है। औरतों ने गोल गप्पे की जात का सबसे ज्यादा उपयोग किया और इसी तरह राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बांड का इस्तेमाल किया। दोनों की तासीर में खाने वाले का ललचाना लिखा हुआ है। न बेचने वाले के पास और न खरीदने वाले के पास कभी गोल गप्पा बचा और अब वहीं स्थिति इलेक्ट्रोल बांड की है। जिन्होंने खरीदा, उन्हें यह भी पता नहीं कि रेहड़ी है किसकी और जिन्होंने बेचे उन्हें यह भी मालूम नहीं कि व्यापार है कितना।

खैर गोल गप्पों ने भारत में न समुदाय और न जातीय भेद के आधार पर स्वाद बदला। स्वाद इसकी अस्मिता है, लेकिन बेस्वाद इलेक्ट्रोल बांड की कोई अस्मिता नहीं। पहले यह जिंदा था तब इसकी ताकत का अंदाजा चुनाव आयोग को भी नहीं था। इसकी अस्मिता चुनाव पर भारी थी, बल्कि चुनाव की अस्मिता चुरा कर ही इलेक्ट्रोल बांड ताकतवर बना। खैर उस दिन गोल गप्पे खाकर बुद्धिजीवी ने जैसे ही पार्टी मुख्यालय के सामने खड़ी डकार ली, सामने एक नेता चीखने लगा अब अंगूर नहीं, खट्टे हो गए इलेक्ट्रोल बांड। वाकई वहां इलेक्ट्रोल बांड के स्वाद से कई नेता अब दांत खट्टे कराने से बचकर भाग रहे थे। आगे नेता, पीछे बांड, दोनों के पीछे बुद्धिजीवी और सबसे पीछे देश भाग रहा था। कौन किसके दांत खट्टे करने से बच रहा था, यह किसी को मालूम नहीं था। अंततः सबसे पहले देश थक कर रुक गया, फिर बुद्धिजीवी थक कर हार गया और इसके बाद इलेक्ट्रोल बांड भी अपनी निलंज्जता के आगे नहीं जा सका, लेकिन नेता इस परिदृश्य से याबव कह रहा था, 'भाइयो-बहनो! मैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भाग रहा हूँ, मेरे हाथ की सफाई देओ, मैं अकेला रहा, जो बह गये भ्रष्टाचारी थे।' बुद्धिजीवी ने देश को समझाना चाहा कि उसका इरादा नेताओं से भिन्न है। यह सुनकर इलेक्ट्रोल बांड ने कांपते-कांपते और जान देते हुए कहा, 'मैं इसलिए देश थक कर रुक गया, फिर बुद्धिजीवी ने फिर एक प्रयास किया। सांत्वना दी कि भ्रष्टाचार के आरोप में चुनावी बांड मर गया, लेकिन देश दूर से राष्ट्र की बात कर रहे नेता से डर रहा था, क्योंकि इस बार भी उसकी ही जेब कटी थी।

### कुलभूषण उपमन्यु

भारत में 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसे हम प्राप्त कर सकेंगे। किंतु बड़े ऊर्जा पार्क बनाकर स्थानीय संसाधनों पर कुछ जगहों पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है, जिससे रोजी-रोटी के संसाधन छिन जाते हैं'

1962 में राचेल कार्सन ने 'साइलेंट सर्प्रिंग' नामक पुस्तक लिखी जिसमें पर्यावरण को कीटनाशकों द्वारा हो रहे नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। कीटनाशकों को कुछ मात्रा अनाजों में आ जाती है और खाद्य श्रृंखला में दाखिल हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव मानव जाति के अतिरिक्त अन्य पशु-पक्षियों पर भी पड़ जाता है जिसके कारण कई पक्षी प्रजातियां लुप्त हो रही थीं जिनके बिना वसंत का सौंदर्य ही समाप्त हो रहा है। पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि बेस्ट सेलर बन गई। इससे अमरीका में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। 1969 में जब दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर खनिज तेल दुर्घटनावाश गिर गया तो सेनेटर गेलोर्ड नेल्सन ने उस क्षेत्र का दौरा करके समुद्री जीवों की तबाही देखी, जो समुद्र के पानी पर तेल के फैलने के कारण हुई थीं। नेल्सन ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए 'टीच इन' कार्यक्रम कोलेजों में आयोजित किए। डेनिस इस और अन्य आंदोलनकारियों के साथ मिल कर इस जागरूकता अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर रफैलाने का निश्चय किया गया, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर की गई और इस दिन को पृथ्वी दिवस का नाम दिया गया। यानी पृथ्वी के स्वास्थ्य की चिंता करने का दिन। इस



कार्यक्रम को भारी जनसमर्थन मिला। इससे बने दबाव के चलते ही अमरीका में 'शुद्ध वायु कानून' बनी और वायु का प्रदूषक बनता जा रहा है। जर्मनी पर पड़े हुए प्लास्टिक से धूप के कारण अपर्दन से टूट कर सूक्ष्म कण मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करने का काम करते हैं। पानी में मिल कर मछलियों के शरीर में पहुंच कर खाद्य श्रृंखला का भाग बन कर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाते हैं। जलाए जाने पर वायु में अनेक विषैली गैसें वायुमंडल में छोड़े हैं जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरें पैदा हो रहे हैं। प्लास्टिक दैनिक जीवन का ऐसा भाग बन गया है कि इससे बचना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, पुनर्चक्रण,

इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय वस्तु 'पृथ्वी ग्रह बचाने प्लास्टिक' रखा गया है। प्लास्टिक मिट्टी, पानी और वायु का प्रदूषक बनता जा रहा है। जर्मनी पर पड़े हुए प्लास्टिक से धूप के कारण अपर्दन से टूट कर सूक्ष्म कण मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करने का काम करते हैं। पानी में मिल कर मछलियों के शरीर में पहुंच कर खाद्य श्रृंखला का भाग बन कर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाते हैं। जलाए जाने पर वायु में अनेक विषैली गैसें वायुमंडल में छोड़े हैं जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरें पैदा हो रहे हैं। प्लास्टिक दैनिक जीवन का ऐसा भाग बन गया है कि इससे बचना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, पुनर्चक्रण,

और जो बच जाए उसको उत्तम धुआं रहित प्रचलन तकनीक से ताप विद्युत बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इससे भी थोड़ा गैस सफलता नहीं मिली है, जिसके लिए अतिरिक्त वैज्ञानिक शोध की जरूरत है ताकि रासायनिक विधि के बराबर ही उत्पादन करके दिखाया जाए और अन्न सुरक्षा की चुनौती पर कोई खतरा आने की चिंता न रहे। जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की है।

उसके पास जो तकनीक है उसमें केवल दशमलव दो (.2) प्रतिशत ही गैस उत्सर्जन होता है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पैकिंग सामग्री तैयार करना नवाचार की दूसरी चुनौती है। गांव में भी अब तो प्लास्टिक कचरे के अंधार लगते जा रहे हैं। अधुनिक दैनिक प्रयोग की तमाम वस्तुएं प्लास्टिक में ही पैक होकर आ रही हैं। प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए यह जरूरी है कि प्लास्टिक और अन्य सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाए और कबाड़ी को दिया जाए। जो बच जाए उसे निबटाने के दूसरे सुरक्षित तकनीकी उपायों की सरकारें व्यवस्था करें। एक विचार यह भी जोर पकड़ रहा है कि जो पैदा करें, वही कचरे के प्रबंधन का जिम्मेदार ठहराया जाए, ताकि ये पैकिंग करके सामान बेचने वाली कंपनियां प्लास्टिक सामग्री एकत्रित करवा कर वापस लें और रिसाइक्लिंग के लिए हानिकारक बन जाते हैं। जलाए जाने पर वायु में अनेक विषैली गैसें वायुमंडल में छोड़े हैं जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरें पैदा हो रहे हैं। प्लास्टिक दैनिक जीवन का ऐसा भाग बन गया है कि इससे बचना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, पुनर्चक्रण,

विकसित करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। भारत में इस दिशा में कुछ काम होना शुरू भी हुआ है, किन्तु इसे अभी तक मुख्य धारा बनाने में सफलता नहीं मिली है, जिसके लिए अतिरिक्त वैज्ञानिक शोध की जरूरत है ताकि रासायनिक विधि के बराबर ही उत्पादन करके दिखाया जाए और अन्न सुरक्षा की चुनौती पर कोई खतरा आने की चिंता न रहे। जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की है। हमारे देश में कुल विद्युत उत्पादन 428 गीगावाट है, जिसमें से 71 फीसदी कोयले और जीवाश्म ईंधन से हो रहा है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन 168.96 गीगावाट है, जिसमें से 42 गीगावाट जल विद्युत का उत्पादन है। किन्तु जल विद्युत भी जब बड़े बांधों के माध्यम से बनाई जाती है तो जलाशयों में बाढ़ से संचित जैव पदार्थ आक्सीजन रहित सडन द्वारा मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन कार्बन डाईआक्साइड से छह गुणा ज्यादा वैश्विक तापमान वृद्धि का कारक है। इसलिए एक सीमा से ज्यादा जल विद्युत का प्रसार भी ठीक नहीं। सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है। भारतवर्ष में पिछले कुछ सालों में सौर ऊर्जा उत्पादन में अच्छा काम हुआ है। भारतवर्ष में 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आशा है इसमें हम प्रगत सकेंगे। किन्तु बड़े ऊर्जा पार्क बना कर स्थानीय संसाधनों पर कुछ जगहों पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है, जिससे कई समुदायों की रोजी-रोटी के संसाधन छिन जाते हैं। इसके विरुद्ध कई आवाजें उठती रहती हैं और संघर्ष खड़े हो जाते हैं। इन जायज संघर्षों का अक्षर शासन और प्रशासन स्थानीय समुदायों की कठिनाई को समझकर समाधान नहीं करते।

# 'खामोश चुनाव' के मायने

आम चुनाव, 2024 के प्रथम चरण का मतदान कई मायनों में अप्रत्याशित रहा है। कुल मतदान शनिवार की रात्रि 11 बजे तक करीब 65.5 फीसदी रहा। यह 2019 की तुलना में 4 फीसदी कम रहा है। सबसे अधिक मतदान संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में 84.16 फीसदी किया गया। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान हुए, लेकिन फिर भी 2019 की तुलना में 2 फीसदी तक कम हुए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 फीसदी मतदान ज्यादा किया गया। जम्मू-कश्मीर सरीखे संवेदनशील क्षेत्र में 68.27 फीसदी मतदान शानदार माना जा सकता है, लेकिन वहां भी 2019 से 1.88 फीसदी मतदान कम हुआ। सबसे कम मतदान बिहार की सीटों पर 49 फीसदी से कुछ ज्यादा रहा, लेकिन 4 फीसदी कम मतदाता वोट देने पर संतुष्ट है। उप और उत्तराखंड जैसे भाजपा वर्चस्व के

राज्यों में 5-6 फीसदी मतदान कम किया गया। मध्यप्रदेश, राजस्थान और मिजोरम आदि राज्यों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। इनसे भाजपा के 370 और 400 पार वाले लक्ष्यों को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि भाजपा उत्तरी भारत में ही शानदार जनादेश के भरोसे है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सब कुछ अनिश्चित है। हालांकि मध्यप्रदेश में 67.76 फीसदी मतदान हुए, लेकिन ये 7.31 फीसदी तक कम रहे। क्या मतदाताओं में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को जनादेश देने का उत्साह और जुनून कम हो गया है? पूर्वोत्तर में दो विरोधाभास उभर कर सामने आए हैं। मणिपुर में हिंसा के बावजूद 72.17 फीसदी लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन टूटी ईवीएम, लुटे बूथ, फटी वीवीपेट पर्चियों के चित्र मणिपुर में ही देखे गए हैं, जिनसे मतदान के दौरान हालात के अनुमान लगाए जा सकते

हैं। पूर्वोत्तर में ही नागालैंड राज्य में 4 लाख मतदाताओं से अधिक, राज्य के करीब 30 फीसदी वोटों ने, 6 जिलों की 20 विधानसभा सीटों पर, बहिष्कार के कारण एक भी वोट नहीं डाला। वे अधिक स्वायत्तता वाले अलग क्षेत्र की मांग करते रहे हैं और केंद्र सरकार फिलहाल उसमें नाकाम रही है, लिहाजा उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था। फिर भी 56.91 फीसदी मतदान हुआ। बेशक 2019 की तुलना में बह 26 फीसदी कम रहे। मणिपुर में भी 10.52 फीसदी मतदान कम हुआ। समग्रता में देखें, तो आम चुनाव के प्रथम चरण में 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करना था, लेकिन 6.12 करोड़ भारतीयों ने वोट ही नहीं डाले। यह चुनाव के प्रति उदासीनता है या मतदाताओं को चुनाव दिशाहीन, अर्थहीन लगते हैं? यह सोच लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ भी है।

जितना मतदान किया गया है, वह न तो सरकार के खिलाफ माना जा सकता है और न ही विपक्ष को चुनने के प्रति उत्साही और उत्सुक लगता है। किसी भी तरफ 'लहर' महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता है मानो औसत मतदाता ने यह धारणा बना ली है कि मोदी को ही आना है! यह सोच कर ही मतदाता पोलिंग स्टेशन से तटस्थ रहा है। कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों की खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने भी मोदी को ही सौरी बार प्रधानमंत्री मान लिया है, लिहाजा कोई भी धुवीकरण दिखाई नहीं दिया। हमने मतदान के इस चरण को 'खामोश और भ्रमित चुनाव' माना है। कुछ जगह की खबरें हैं कि भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं पर मतदान कराने और चुनावी जीत तय कराने की जिम्मेदारी थी, वे आराम से पंचतारा होटल में खाना खाते रहे। यदि ऐसा है, तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनके आह्वान वॉच पर लगते

हैं। इस चरण से पहले 38 फीसदी पात्र युवाओं ने ही निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराया। साफ है कि युवा चुनाव के प्रति उत्साही नहीं हैं। बहरहाल अभी तो मतदान के छह और चरण शेष हैं। गर्मी का मौसम भी ज्यादा गर्म और लू वाला होना है। कई जगह मई में ही बारिश की शुरुआत हो सकती है, लिहाजा मौसम के कारण इतना मतदाता घर से न निकले, समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि चुनाव प्रथममंत्री मोदी पर ही केंद्रित रखा गया है, लिहाजा बेरोजगारी, महंगाई, राम मंदिर सरीखे मुद्दे शांत से लगते रहे। क्या मतदान का यह 'ठंडापन' यही समाप्त होगा, यह अहम सवाल है। नागालैंड में बड़े पैमाने पर चुनाव का बहिष्कार लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इस राज्य की मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिए था। न जाने केंद्र सरकार कब तक मणिपुर व नागालैंड जैसे राज्यों की अनदेखी करती रहेगी।

# अयोध्या ने बढ़ाया आध्यात्मिक पर्यटन का बाजार? विदेश नहीं, धर्म स्थलों पर जाना ज्यादा पसंद कर रहे लोग

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के लोग अब घूमने-फिरने में पहले के मुकाबले अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे खासकर अयोध्या उज्जैन और बद्रीनाथ जैसे आध्यात्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं। इन जगहों के लिए सर्च में बड़ा उछाल देखा गया है। फैमिली ट्रेवल बुकिंग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है जो एक साल में तीन या इससे अधिक बार ट्रिप पर जा रहे हैं।

नई दिल्ली। भारत के लोग अब घूमने-फिरने में पहले के मुकाबले अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे खासकर अयोध्या, उज्जैन और बद्रीनाथ जैसे आध्यात्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं। इन जगहों के लिए सर्च में बड़ा उछाल देखा गया है। यह बात MakeMyTrip इंडिया ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट में सामने आई है।

इस ट्रेवल प्लेटफॉर्म ने अपने 10 करोड़ से अधिक सालाना एक्टिव यूजर्स के पसंद के हिस्से में यह जानकारी दी। MakeMyTrip की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे लोगों की संख्या में 25 प्रतिशत इजाफा हुआ है, जो एक साल में तीन या इससे अधिक ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर ट्रेवल में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो



इसकी बड़ी वजह है, आध्यात्मिक यात्राओं में बढ़ती दिलचस्पी। MakeMyTrip की रिपोर्ट की माने, तो 2021 के मुकाबले 2023 में आध्यात्मिक पर्यटन (spiritual tourism) में 97 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया। अयोध्या के लिए सर्च 585 प्रतिशत बढ़ी

खासकर, टियर 2 और टियर 3 के लोग ऐसी डेस्टिनेशन (Destinations) खोज रहे हैं, जिनकी आध्यात्मिक अहमियत हो। MakeMyTrip की रिपोर्ट बताती है कि 2022 की तुलना में 2023 के दौरान अयोध्या के लिए सर्च करने वाले यात्रियों की संख्या 585 प्रतिशत का भारी-भरकम उछाल आया। इसी

तरह उज्जैन और बद्रीनाथ के लिए भी सर्च में क्रमशः 359 प्रतिशत और 343 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि लोग वोकेंड पर भी घूमना काफी पसंद कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सर्च में 2022 की तुलना में 2023 में 131 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

वहीं, ऊटी और मुन्नार जैसे हिल स्टेशन जैसे देश के दक्षिण हिस्से भी काफी पसंद आ रहे हैं। फैमिली ट्रेवल बुकिंग में भी भारी उछाल। इंटरनेशनल ट्रेवल के शौकीन सैलानी भी कम नहीं हैं। लोगों को खासकर दुबई, बैंकॉक और सिंगापुर जाना सबसे अधिक पसंद है। ये तीनों सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले

डेस्टिनेशन बने हुए हैं। वहीं, लंबी दूरी के लिए लोगों को पसंदीदा डेस्टिनेशन लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क हैं। फैमिली ट्रेवल बुकिंग भी तेजी से बढ़ रही है। इसमें 2022 की तुलना में 2023 में 64 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं, इस दौरान सिंगल ट्रेवल की बुकिंग सिर्फ 23 प्रतिशत बढ़ी है।

## सारे आर्थिक समीकरण भारत के हक में, क्या बरकरार रह पाएगी 7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट?

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। कई प्रतिष्ठित ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को रिवाइज्ड करके बढ़ाया है। अब रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के मंबर शशांक भिडे का कहना है कि भारत मौजूदा वित्त वर्ष और उसके बाद भी सात प्रतिशत ग्रोथ रेट को बनाए रख सकता है। उन्होंने इसकी कई वजहें भी गिनाई हैं।

नई दिल्ली। पिछले कई तिमाहियों से भारत की आर्थिक विकास दर काफी बेहतर रही है। रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के मंबर शशांक भिडे का मानना है कि भारत मौजूदा वित्त वर्ष और उसके बाद भी सात प्रतिशत ग्रोथ रेट को बनाए रख सकता है।

भारत के पक्ष में समीकरण शशांक भिडे ने कहा कि मानसून खेती के अनुकूल है, जिससे उपज बेहतर रहने की संभावना है। वहीं भारत का वैश्विक व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा है। ऐसे में भारत के लिए 7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट बरकरार रखना मुमकिन है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी दमदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 8 फीसदी के करीब रहने का



अनुमान लगाया जा रहा है।

**बढ़ाना होगा उत्पादन**

MPC मंबर भिडे का कहना है कि अगर भारत को लंबी अवधि में खाने-पीने की चीजों का दाम स्थिर रखना है, तो उत्पादकता में सुधार जरूरत रहेगी। पिछले दिनों थोक महंगाई के आंकड़े जारी हुए थे। इसमें सालाना आधार पर मामूली बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन, आलू-प्याज जैसी सब्जियों के दाम में भारी उछाल आया है। हालांकि, अल्पकालिक समस्या

**वैश्विक तनाव बढ़ा सकते हैं चुनौती**



भारत के लिए किस मोर्चे पर चुनौती सबसे अधिक है। इस सवाल पर भिडे ने वैश्विक माहौल का जिक्र किया।

“ग्लोबल डिमांड में सुधार की रफ्तार काफी सुस्त है। साथ ही, सप्लाय चैन के साथ भी दिक्कत है। अगर मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव जल्दी खत्म नहीं होता, तो इससे डिमांड-सप्लाय का समीकरण बिगड़ेगा और कीमतें बढ़ने का जोखिम भी रहेगा। कई बार बाढ़ या सूखे जैसी कुदरती आपदाओं से भी कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। हमें इनका प्रभाव कम करने की तैयारी भी करने होगी।

**IMF बढ़ा चुका ग्रोथ का अनुमान**

पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया। IMF के मुताबिक- भारत में कामकाजी उम्र वाली आबादी बढ़ रही है। साथ ही, घरेलू मांग भी दमदार बनी हुई है। इनके दम पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है।

## सिंगापुर के बाद अब इस देश में भी बैन हुए एमडीएच और एवेरेस्ट के ये मसाले, लोगों से इस्तेमाल न करने की अपील

भारत के लोकप्रिय मसाला ब्रांड एमडीएच (MDH) और एवेरेस्ट (Everest) के कई मसालों को सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। अब इन कंपनी के कुछ मसालों को हांगकांग में भी बैन किया गया है। दरअसल हांगकांग सरकार के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी (CFS) ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड कैमिकल पाया गया है जो सेहत के लिए हानिकारक है।

नई दिल्ली। कुछ दिन पहले सिंगापुर के फूड एजेंसी (SFA) ने एक रिपोर्ट पेश किया था। इस रिपोर्ट के बाद सिंगापुर में भारत के लोकप्रिय मसाला ब्रांड एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड (MDH) और एवेरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (Everest) के कुछ मसालों को बैन कर दिया गया। अब इन मसालों पर हांगकांग ने

भी एक्शन लिया है।

इन दोनों ब्रांड के मसालों में हानिकारक कैमिकल पाने के बाद यह एक्शन लिया गया है। हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की सरकार के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी (CFS) ने इन मसालों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार इन मसालों में कार्सिनोजेनिक कोटनाशक एथिलीन ऑक्साइड कैमिकल पाया गया है। यह कैमिकल सेहत के लिए काफी हानिकारक है।

इस रिपोर्ट के आने के बाद हांगकांग सरकार ने इन मसालों को बैन कर दिया और लोगों से इन मसालों का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। बता दें कि सीएफएस की प्रेस रिलीज 5 अप्रैल 2024 को जारी हुई थी।

**ये मसाले हुए बैन**  
सेंटर फॉर फूड सेफ्टी (CFS) ने एमडीएच का मद्रास करी पाउडर (MDH Madras curry powder), एमडीएच सांभर मसाला (MDH Sambhar Masala), एमडीएच करी पाउडर (MDH Curry Powder), एवेरेस्ट का

फिश करी मसाला (Everest Fish Curry Masala) को बैन किया है।

पिछले हफ्ते सिंगापुर फूड एजेंसी (एसएफए) ने भी एमडीएच और एवेरेस्ट के मसालों को लेकर रिपोर्ट पेश किया था। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि इन मसालों में भी कार्सिनोजेनिक ऑक्साइड पाया गया है जो मानव के उपभोग के लिए नहीं है। बता दें कि एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टीसाइड है। अगर मानव इसका सेवन करता है तो उन्हें कैंसर होने की संभावना अधिक होती है।

पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन फूड रेगुलेशन के अनुसार मानव को कोटनाशक अवशेषों वाले भोजन तभी बेचे जा सकते हैं जब वह उनके सेहत के लिए हानिकारक न हो। अगर



वह मानव के लिए हानिकारक होने वाले पेस्टीसाइड बेचते हैं और पकड़े जाते हैं तो उन्हें 50,000 डॉलर का जुर्माना और 6 महीने की कैद हो सकती है।

वर्ष 2023 में भी अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने भारतीय मसाला ब्रांड एवेरेस्ट के प्रोडक्ट को हटाने का आदेश दिया था।

## प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सरकार देती है 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस



नई दिल्ली। भारत सरकार सभी वर्गों को आर्थिक लाभ देने के लिए कई स्कीम चला रही है। इन स्कीम में से एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) है।

**PMJJBY के बारे में**  
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) प्लान है। इसका लाभ मृत्यु के बाद पॉलिसी होल्डर के परिवार को मिलता है।

इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर की बीमारी, दुर्घटना और किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। हालांकि, अगर योजना की अवधि पूरी होने तक निवेशक को कुछ नहीं होता है तो उसे लाभ नहीं दिया जाता है।

इस स्कीम का फायदा 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। इस योजना में आवेदन के बाद निवेशक चाहें तो ऑटो डेबिट (Auto-Debit) का भी इस्तेमाल कर सकता है।

इस स्कीम में सरकार कम राशि में इंश्योरेंस उपलब्ध करवाती है। इसमें कोई भी नागरिक मात्र 436 रुपये सालाना का निवेश करके 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस ले सकता है। 2022 से पहले पॉलिसी को खरीदने के लिए केवल 330 रुपये का भुगतान करना होता था, बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया। इस पॉलिसी में दिये जाने वाला प्रीमियम 1 जून से लेकर अगले साल 31 मई तक के लिए मान्य रहता है।

**कैसे करें आवेदन**  
आप आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक या फिर एलआईसी (LIC) ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

**ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी**  
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card), पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट पासबुक (Bank Account Passbook) और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

## महंगा हुआ जोमैटो से खाना मंगाना, 25 प्रतिशत बढ़ा प्लेटफॉर्म चार्ज; यह सर्विस भी हुई बंद

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने प्लेटफॉर्म चार्ज 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

इसका मतलब है कि अब जोमैटो से खाना मंगाना थोड़ा महंगा पड़ेगा। जोमैटो के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अब ग्राहकों को हर ऑर्डर पर चार के बजाय पांच रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में देने होंगे। यह बढ़ोतरी शनिवार (20 अप्रैल) से लागू भी हो गई है। दीपेंद्र गोयल की कंपनी जोमैटो सालाना लगभग 85-90 करोड़ डॉलर डिलीवर करता है। इस हिसाब से प्लेटफॉर्म फीस 1 रुपया प्रति ऑर्डर बढ़ाने से जोमैटो के EBITDA में सालाना 85 से 90 करोड़ रुपये का इजाफा होने का अनुमान है।

जोमैटो ने अपनी 'इंटरसिटी लीजेंड्स' सर्विस को भी बंद कर दिया है। कंपनी इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विस के जरिए प्रमुख शहरों के बड़े रेस्टोरेंट्स से दूसरे शहरों के ग्राहकों तक ऑर्डर डिलीवर करती थी।



## निवेशकों को खूब पसंद आया देश का सबसे बड़ा FPO, आखिरी दिन इतना गुना हुआ सब्सक्राइब

Vodafone Idea FPO टेलीकॉम ऑपररेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltds) की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। कंपनी कर्ज में डूबी है। कर्ज से निपटने के लिए कंपनी ने 18000 करोड़ रुपये की फॉलो-ऑन ऑफरिंग (एफपीओ) पेश की थी। आज कंपनी के एफपीओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। सोमवार को वोडाफोन आइडिया का एफपीओ 3.3 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया।

नई दिल्ली। टेलीकॉम ऑपररेटर वोडाफोन

आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltd's) कर्ज से डूब गई है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपये की फॉलो-ऑन ऑफरिंग (FPO) पेश किया था। इसमें कंपनी ने शेयर 10-11 रुपये के प्राइस बैंड निर्धारित किया था।

22 अप्रैल 2024 को इस एफपीओ का आखिरी दिन था। निवेशकों को कंपनी का एफपीओ काफी पसंद आ रहा है। इस एफपीओ में अधिकतम संस्थागत निवेशकों ने पैसे लगाए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोमवार को वोडाफोन आइडिया का एफपीओ 3.3 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया।

स्टॉक एक्सचेंजों की जानकारी के अनुसार एफपीओ के आखिरी दिन 2.30 बजे 1,260 करोड़ के इश्यू आकार के मुकाबले 4,212.56 करोड़ शेयर मांगे गए थे। वैसे फाइल नंबर मार्केट बंद होने के बाद पता चलेंगे।

योग्य संस्थागत खरीदारों (Qualified

institutional buyers) ने आरक्षित 360 करोड़ शेयरों में से 8.71 गुना शेयरों की मांग की। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों ने निर्धारित 270 करोड़ शेयरों में से 2.7 गुना शेयरों के लिए बोली लगाई। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी खुदरा निवेशकों की थी। रिटेल इन्वेस्टर ने 630 करोड़ शेयरों में से केवल 56 प्रतिशत ही खरीदे गए। कंपनी के शेयर आज दोपहर बीएसई पर शेयर के 12.44 रुपये के ट्रेडिंग मूल्य से कम है।

**कंपनी ने इतने शेयर बेचे**  
वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते पहले संस्थागत निवेशकों को 5,400 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। एंकर बुक आवंटन के दौरान निवेश फर्म जीक्यूजी और फिडेलिटी ने अधिकांश शेयर खरीदे। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले, भारतीय बाजार में सबसे बड़ा एफपीओ 2020 में यस बैंक द्वारा 15,000 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री थी।



# “पर्यावरण पाठशाला : कबूतरों को अत्यधिक भोजन देने के खतरे: अंकुर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कबूतरों को खाना खिलाना एक हानिरहित गतिविधि की तरह लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम साधारण पक्षी अवलोकन से कहीं आगे तक जाते हैं। जबकि यह अधिनियम अपने आप में सड़क सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है, ड्राइवरो और पैदल चलने वालों का ध्यान भटक जाता है, सड़क के किनारे स्थानों पर कबूतरों को खाना खिलाने के खतरनाक प्रभावों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं से परे, कबूतरों को जरूरत से ज्यादा खाना खिलाने से उनकी बीट सेकेंडर क्षेत्रों में जमा हो जाती है, जिससे बीमारी के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। कबूतर की बीट में क्रिप्टोकोकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और सिटाकोसिस सहित कई रोगजनक होते हैं, जो सभी मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।

हिस्टोप्लाज्मोसिस, एक श्वसन रोग, कबूतरों की बीट को साफ करते समय बने धूल के कणों को सांस के माध्यम से अंदर लेने से हो सकता है। इसी तरह, क्रिप्टोकोकोसिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और अगर इलाज न किया जाए तो गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। कबूतर की बीट से जुड़ी अन्य बीमारियों में कैडिडिआसिस, सेंट लुइस



एन्सेफलाइटिस, साल्मोनेलोसिस और विभिन्न संक्रमण शामिल हैं।

इसके अलावा, घरेलू और जंगली कबूतर दोनों ही इन खतरनाक एजेंटों के वाहक के रूप में काम

करते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा और बढ़ जाता है। कबूतरों द्वारा ले जाए गए एक्टोपारासाइट्स भी मनुष्यों को परेशान कर सकते हैं, जो पहले से ही खतरनाक स्थिति में चिंता की एक और परत जोड़ देते हैं।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, सड़क किनारे इलाकों में कबूतरों को जरूरत से ज्यादा खाना खिलाने को हतोत्साहित करके मूल कारण का समाधान करना महत्वपूर्ण है। नियमों और जन जागरूकता अभियानों को लागू करने से व्यक्तियों को इस प्रतीत होने वाली अहानिकर गतिविधि से जुड़े खतरों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, कबूतरों की बीट के संयोजन को कम करने और बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को नियोजित किया जाना चाहिए।

हालांकि कबूतरों को दाना डालना हानिरहित लग सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में किए जाने पर यह महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा करता है, खासकर सड़क के किनारे वाले स्थानों पर। अत्यधिक भोजन को हतोत्साहित करने और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए सक्रिय उपाय करके, समुदाय अपने निवासियों और पर्यावरण दोनों को कबूतरों

## उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी 24 अप्रैल को भीलवाड़ा शहर में करेगी रोड शो

लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में शहर के मुख्य बाजारों में होगा सघन जनसंपर्क

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी 24 अप्रैल को भीलवाड़ा विधानसभा अंतर्गत शहर के मुख्य बाजारों में रोड शो कर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में सघन जनसंपर्क द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान के साथ भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील करेंगी। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी उनके साथ रहेंगे।

जिला प्रवक्ता अंकुर बोरादिया ने बताया कि रोड शो एवं जनसंपर्क कार्यक्रम में सांसद, जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, नगर परिषद सभापति, विधानसभा प्रभारी, संयोजक भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का रोड शो एवं जनसंपर्क कार्यक्रम 24 अप्रैल बुधवार को प्रातः 9:00 बजे दूधधारी गोपाल मंदिर, सांगानेरी गेट से प्रारंभ होकर शहीद चौक, धानमंडी, बड़ा मंदिर, सराफा बाजार, गुलमंडी, भोपाल क्लब चौराहा, नया बाजार, सुभाष मार्केट, गोल प्याऊ चौराहा, सदर बाजार हाते हुए रेलवे स्टेशन चौराहा स्थित अंबेडकर सर्किल पर संपन्न होगा। भारतीय जनता पार्टी के



प्रताप मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जादौन, शास्त्री मंडल अध्यक्ष पीयूष डांड, गणेश मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिंगीवाल, सुभाष मंडल अध्यक्ष मनीष पालीवाल ने ज्यादा संख्या में शहरवासियों से रोड शो एवं जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। कार्यक्रम में भीलवाड़ा शहर के समस्त जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, जिला एवं मंडल के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ पदाधिकारी, पार्षद एवं पूर्व पार्षद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं शहर के गणमान्य नागरिक एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहेंगे।

## नरिंदर बहल को शिरोमणि अकाली दल सेंटर कांस्टीट्यूटिंग का प्रभारी नियुक्त किया गया, व्यापार उद्योग ने गर्मजोशी से नरिंदर बहल स्वागत किया



अमृतसर (साहिल बेरी) शिरोमणि अकाली दल को आज अमृतसर सिटी सेंटर कांस्टीट्यूटिंग से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली जब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया श्री अनिल जोशी जी उम्मीदवार शिरोमणि अकाली दल लोकसभा श्री अमृतसर ने श्री नरेंद्र बहल जी को अध्यक्ष आरटी एसोसिएशन अमृतसर नियुक्त किया जो लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल की सेवा कर रहे थे, केंद्र निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी और उद्योग समन्वयक और हरपाल सिंह राजिंदर सिंह मरवाहा, हरपाल सिंह अहलूवालिया राजीव दुग्गल अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग अमृतसर मनदीप सिंह जी पवन शर्मा महासचिव, गुरप्रीत सिंह नारंग विने बय्याला बांबी जी और अन्य ने नरेंद्र बैल जी को नियुक्त और सम्मानित किया इस अवसर पर राजिंदर सिंह मरवाहा समन्वयक व्यापार उद्योग और हरपाल सिंह अहलूवालिया ने संयुक्त रूप से कहा कि नरेंद्र बहल-श्री अनिल जोशी को सेंटर कांस्टीट्यूटिंग लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त मिलेगी।

**बोर्डर' पर नहीं जा सकते, बूथ' पर तो जा सकते हैं ना ?**  
अगर मतदान के दिन आपकी उंगली पर स्याही का निशान नहीं है तो अगले 5 साल तक आपको किसी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है

## 81 दिन के लिए बंद हुए बैंड-बाजा-बारात, जाने क्यों

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश में 21 अप्रैल से शादियों पर ब्रेक लग गया है और 10 जुलाई तक शादियां बंद रहेंगी यानी अगले 81 दिन शादियों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेगा, यहां पहले से ही सूर्य का गोचर हो रहा है और मेष राशि में प्रवेश करते ही शुक्र अस्त हो जाएंगे लेकिन शुक्र के अस्त होने से 3 दिन पहले 21 अप्रैल से ही शुक्र-बाल्यत्व दोष से घिर जाएंगे शुक्र 7 जुलाई तक अस्त रहेंगे और 7 जुलाई को उदय होने के बाद 10 जुलाई तक बाल्यत्व दोष के दायरे में रहेंगे लिहाजा देश में 11 जुलाई से शादियों का सीजन शुरू होगा। इस बीच 6 मई को गुरु भी वृषभ राशि में अस्त होंगे और 4 जून को उदय होंगे। यह दोनों ही ग्रह मांगलिक कार्यों के लिए शुभ होते हैं और यदि दोनों ग्रह अस्त हों तो मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शुक्र के अस्त होने का विचार खास तौर पर शादी के लिए किया जाता है क्योंकि शुक्र को ही ज्योतिष में शादी का काजक ग्रह माना जाता है। यदि शुक्र के अस्त होने की स्थिति में शादी कर ली जाए तो वैवाहिक जीवन में परेशानी पेश आती है, लिहाजा शुक्र के अस्त होने के समय देश भर में हिंदू समाज में शादियां वर्जित होती हैं। देश में शादियों का सीजन ठप होने के कारण अब अगले अर्द्धाई महीने तक कपड़े और ज्वेलरी के कारोबार के अलावा



आएगा। नवम्बर महीने में होंगी सबसे ज्यादा शादियां शुक्र के उदय होने के बाद इस साल में विवाह मुहूर्त 11 जुलाई को होगा, जबकि साल का आखिरी शुभ मुहूर्त 11 दिसम्बर का रहेगा। इस बीच नवम्बर महीने में शादी के सबसे ज्यादा मुहूर्त निकल रहे हैं। नवम्बर में 15 दिन, अगस्त में 12, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 और सितम्बर में शादियों के 9 मुहूर्त हैं। इस साल में 18 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक पितृ पक्ष होने के कारण विवाह शादियों जैसे मांगलिक कार्य बंद रहेंगे और फिर से 2 अक्टूबर को पितृ पक्ष खत्म होने के बाद शुरू होंगे।

## याद रखें: चार्ली चैपलिन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया

उन्होंने हमें 4 कथन छोड़े:

- (1) इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ तक कि हमारी समस्याएँ भी नहीं।
- (2) मुझे बारिश में चलना पसंद है, क्योंकि कोई भी मेरे आँसु नहीं देख सकता।
- (3) जीवन का सबसे बर्बाद दिन वह होता है जब हम हँसते नहीं हैं।

(4) दुनिया के छह सबसे अच्छे डॉक्टर...

1. धूप,
2. आराम,
3. व्यायाम,
4. आहार,
5. आत्म-सम्मान
6. दोस्त।

उन्हें अपने जीवन के सभी चरणों में रखें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें... यदि आप चौंद को देखते हैं तो आपको ईश्वर की सुंदरता दिखाई देगी... यदि आप सूर्य को देखते हैं तो आपको ईश्वर की शक्ति दिखाई देगी... यदि आप दर्पण में देखते हैं, तो आपको ईश्वर की

सर्वश्रेष्ठ रचना दिखाई देगी। तो फिर इस पर विश्वास करें। हम सभी पर्यटक हैं, ईश्वर हमारे ट्रेवल एजेंट हैं जिन्होंने पहले से ही हमारी यात्रा कार्यक्रम, बुकिंग और गंतव्य बना रखे हैं... उन पर विश्वास करें और जीवन का आनंद लें। जीवन बस एक यात्रा है!

## डॉ. मरवाहा फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन, फिजियोथेरेपी आज की जरूरत है - डॉ. मनजोत सिंह



अमृतसर (साहिल बेरी) अमृतसर के गार्डन एक्लेव में डॉ. मरवाहा फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिसमें अमृतसर के विभिन्न डॉक्टर भाग ले रहे हैं। डॉ. मरवाहा ने कहा कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा क्षेत्र की एक बहुत ही उन्नत शाखा है जिसमें बिना किसी दवा के मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। थैरेपी ट्रेनिंग थैरेपी और विभिन्न व्यायाम प्रोटोकॉल वर्ल्ड सिख चैबर के अध्यक्ष ऑफ कॉमर्स

अमृतसर सरदार राजिंदर सिंह मरवाहा जी ने कहा कि यह केंद्र अमृतसर का पहला डिजिटल और उन्नत फिजियोथेरेपी केंद्र है जिसमें मरीजों का इलाज इलेक्ट्रोथेरेपी और व्यायाम थैरेपी से किया जाता है। गुरशरण सिंह नारंग, डॉ. दिनेश कुमार, डॉ. अमरजीत सिंह सचदेवा व डॉ. प्रभजोत सिंह, फिल्म अभिनेता जसपाल भट्टी, मैडम जसविंदर सोहल, डॉक्टर अंग्रेज सिंह, मैडम वीना, जतिंदर कौर विशेष रूप से शामिल हुए।

## ग्रेजुएशन के छात्र अब पीएचडी के लिए करें अप्लाई

परिवहन विशेष | एसडी सेठी।

चार साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद छात्र अब नेट एजाम देकर PHD ( पीएचडी ) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके पास पास % प्रतिशत मार्क्स के साथ आनर्स की डिग्री होना अनिवार्य है।

यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमिश्नर ( यूजीसी ) के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि 75 % प्रतिशत अंकों के साथ चार साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर चुके छात्र यूजीसी नेट या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी स्नातक के छात्रों के लिए यह सुविधा नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए साल 2022 से लेकर आया था। लेकिन इसको लेकर कई मानदंड तय किए गए हैं। अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो यूजीसी के इस फैसले को ध्यान से गौर करना चाहिए। यूजीसी के मुताबिक चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे छात्र नेट एजाम देकर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हालांकि छात्रों के पास आनर्स की डिग्री में 75 % प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति, (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीएस) दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 5 % प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी। इससे पहले पीएचडी के



लिए 3 साल का ग्रेजुएशन और कम से कम 55 % प्रतिशत अंक के साथ मास्टर्स डिग्री की जरूरत होती है। लेकिन अब 75 % प्रतिशत अंकों के साथ आनर्स की डिग्री से पीएचडी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में यूजीसी ने (पीएचडी) डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएँ विनियम-2022 के तहत 4 साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम ( एफवाईयू ) को

लॉन्ग किया था। इस प्रोग्राम में छात्र 3 की जगह 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को आनर्स डिग्री कहा जाएगा। यूजीसी के मुताबिक जो छात्र 3 साल में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन्हें 120 क्रेडिट ( अकादमिक घंटों की संख्या के माध्यम से मापा जाता है। जबकि 4 साल में 160 क्रेडिट हासिल करने होंगे। छात्र ग्रेजुएशन में कोन सा कोर्स करेंगे? यह छात्रों

पर निर्भर करेगा। यह पूरी तरह ऑनशनल है। उल्लेखनीय है कि यूजीसी नेट एजाम में विषय चुनने का आशान दिया है। स्टूडेंट्स को किसी भी सबजेक्ट के लिए नेट एजाम देने की अनुमति होगी। चाहे ग्रेजुएशन में किसी दूसरे स्टीम की पढ़ाई की हो। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन में पहले सबजेक्ट में ही नेट एजाम देना जरूरी नहीं होगा।